SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): Sir, I associate myself.

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): Sir, I too am associating myself. I think it is a very serious allegation if it is true. What is happening in our country, I do not know Government has to see to it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Special mentions are over. Now we take up the Statutory Resolution and the Special Court (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Bill, 1992. They are to be discussed together.

STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE SPECIAL COURT (TRAIL OF OFFENCES RELATING TO TRANSACTIONS IN SECURITIES) ORDINANCE, 1992

AND

THE SPECIAL COURT (TRIBAL OF OFFENCES RELATING TO TANSACTIONS IN SECURITIES) BILL, 1992.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): Sir, I beg to move:

> "That this House diaspproves of the Special Court (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Ordinance 1992 (No. 10 of 1992) promulgated by the President on the 6th June, 1992."

श्रीमन, जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है उस उद्देश्य से किसी की मतभिन्नता नहीं हो सकती लेकिन जिस प्रकार से ये बनाया गया है ऐसा लगता है या तो अधूरे मन से बनाया गया है या बहुत जल्दी में बनाया गया है । इसमें बहुत सी कमियां हैं । जब से यह बैंक का [illegible] सिक्योरिटीज की गड़बड़ी सामने आई है तब से सारा देश चिंतित है कि किस तरह से जांच करके जल्दी सही सूचनाएं [illegible] की जाए [illegible] में [illegible] आवश्यकता तो इस बात की थी कि जैसे बिल लाया गया है इसके साथ-साथ इसके नियम भी आने चाहिए थे क्योंकि जब तक रूल्स नहीं बनेंगे तब तक किसी बिल को लागू करना असंभव है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसके अंतर्गत बनने वाले रुल्स आप इस बिल के पास होने के बाद सामने लाएंगे अथवा नहीं ? मेरा आग्रह है कि रुल्स जल्दी से जल्दी बनाए जाने चाहिए लेकिन इसमें एकाध कमियां हैं । महोदय, पेज 2 पर जो सैक्शन 3(2) है उसमें कहा गया है कि—

> "The Custodian may, on being satisfied oil information received that any person has been involved in any offence relating to transactions in securities after the 1st day of April, 1991 and on or before the 6th June, 1992, notify the, name of such person in the Official Gazette."

मैं पूछना चाहता हूं कि यह सीमा आपने बांधी क्यों है ? यदि 6 जून 1992 के बाद कोई घपला, कोई गड़गड़ या जुर्म सामने आता है तो उसको क्यों बरी कर रहे हैं यह विडंबना है कि आपने यह पीरियड बांध दिया है कि इस पीरियड के भीतर जो सामने आएगे उसको कस्टोडियन तय कर सकेगा । दूसरे मैं कोई वकील नहीं हूं लेकिन छोटी मोटी जानकारी मुझे है । इसमें अटैचमेंट की यहां पर व्यवस्था की गई है । लेकिन सब जानते हैं कि अटैचमेंट सिविल प्रोसिजर कोर्ट से गवर्न होता है । अटैचमेंट करने के बाद कोई सिविल प्रोसिजर कोर्ट में चला गया तो मामला वर्षों तक लटका रहेगा । तो मामला जो भी हो वह जल्दी सुलझे यही सरकार की मंशा है । सरकार की मंशा जल्दी सुलझाने की है वह इस बात से प्रकट होती है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपेलेट अथॉरिटी बनाया है, हाई कोर्ट को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट को बनाया है । जो भी जुर्म में पकड़ा गया उसके अटैचमेंट को लेकर सारे मामले लटके रहेंगे तो इस विषय को आप किस प्रकार से सुलझाएंगे यह भी बताने की कृपा करें ।

[Shri Jagdish Prasad Mathur]

श्रीमन, इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो हवेग जैसे सेक्शन 4 में दिया गया है—

"Provided that no contract or agreement shall be cancelled except after giving to the parties to the contract or agreement a reasonable opportunity of being heard."

कोई सीमा बाँध दी जाए, यह जो रीजनेबल पीरियड कहा है इसमें वह चाहेंगे तो किसी को कुछ समय देंगे, किसी को कुछ समय देंगे। तो रीजनेबल की व्याख्या की जानी चाहिए अन्यथा रूल्स के अंदर उसकी स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए।

दूसरी एक चीज इसमें अटपटी मालूम होती है। इसमें कहा गया है—

"The Special Court shall consist of a sitting Judge of the High Court nominated by the Chief Justice of the High Court."

लेकिन आगे पावर्स में कहा गया है—

"...and for the purposes of the said provisions of the Code, the Special Court shall be deemed to be a Court of Session and shall have ..all the powers of a Court of Session."

यह भी विडंबना है कि हाई कोर्ट का जज बैठेगा लेकिन उसके पास अधिकार सेशन कोर्ट के होंगे। आपने हाई कोर्ट को अपेलेट न बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कही है। दूसरी इसमें और भी एक विडंबना है कि—

"While dealing with any other matter brought before it, the Special Court may adopt such procedures as it may deem fit consistent with the principles of natural justice."

तो इसका प्रोसिजर क्या होगा? क्या इस की केवल उनको अथॉरिटी दी गई है या रूल्स में प्रोवाइड करेंगे या क्या करेंगे, यह बताने की कृपा करें।

इसी प्रकार से इस में कहीं नहीं दिया गया है कि कोई मुजरिम पाया जाए तो उसको सज़ा क्या दी जाएगी। मैं समझता हूं कि सैक्यूरिटी ऐक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड आफ इंडिया का जो बिल पास किया है शायद उसी के अनुसार उनको सज़ा दी जाएगी। यह मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा कि सज़ा जो दी जाएगी वह सेबी के अंदर ही दी जाएगी या जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है उसके अंदर दी जाएगी। इसमें कोई सफाई नहीं की गई है कि सज़ा कितनी होगी। इसमें अगर देखें तो अगर सज़ा सेबी को जो ऐक्ट हो गया है उसके सेक्शन 24 में कहा गया है—

"The violation of any rule or provision made thereunder shall be punishable with an Imprisonment which may extend up to one year or a fine or both."

तो इतनी कम सज़ा दी जाएगी इतने बड़े घोटाले के लिए, क्या यह उचित है? मुझे दिखाई देता है कि इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए और इसकी कोई न कोई सफाई दी जानी चाहिए। अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। जहां पर लाइबिलिटीज को पूरा करने का सवाल है:

"The following liabilities shall be paid or discharged in full, as far as may be, in the order as under."

पहले दिया है रेवेन्यू टेक्सेज सरकार के हैं। दूसरा दिया है—

"All amounts due from the persons so notified by the Custodian to any bank or financial institution or mutual fund."

आखिर में दिया है—

"Any other liability as may be specified by the Special Court from time to time."

मतलब क्या है? इसमें किसी बाहुबली आदमी का पैसा लगा हुआ है। जैसे अभी एक केस आया उसके इन्टरेस्ट को लेव नहीं किया गया। मैं पूछना चाहूंगा कि

उनका जो इन्टरेस्ट है, उनका जो हित है उनकी रक्षा करने का आपके पास क्या है ? सरकार ने अपना पैसा तो ले लिया लेकिन जो गरीब का पैसा कहीं लगा हुआ है, मामूली आदमी का पैसा लगा हुआ है और उसमें घपला मिलता है तो अव्वल तो उसका अटेचमेंट करना चाहिए, पैसा मिलेगा कितना मिलेगा, परमात्मा जाने, लेकिन जो भी मिलेगा मामूली आदमी के हित की रक्षा के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए।

अंत में मैं फिर आग्रह करूंगा कि इसको थोड़ा संशोधित करके और जो कमियां हैं उनको दूर करके, रुल्स बनाकर उनको जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि इसको रूल्स कम से कम इस सदन के उठने से पूर्व ही हमारे सामने आ जायेंगे तो इस उद्देश्य की पूर्ति में यह बिल सहायक हो सकता है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the establishment of a Special Court for the trial of offences relating to transactions in securities and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Government received the first interim report of the Janakiraman Committee on the irregularities in the securities transactions of banks and financial institution on 2nd June, 1992. The Government acted promptly in the matter. The President promulgated the Special Court (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Ordinance, 1992 on the 6th of June, 1992. The Ordinance provided for the establishment of a Special Court for the trial of offences relating to transactions in securities and for matters concerned therewith or incidental thereto. Some rules were also framed and notified by the Government on the 6th of June itself. The Government appointed Shri A. K. Menon, Additional Deputy Comptroller and Auditor General as Custodian under Section 3 of the Ordinance on the 6th of June, 1992 itself. Justice S. N. Variava, a sitting Judge of the High Court at Bombay was nominated to head the Special Court, in consultation with the the Chief Justice of the High Court and the Chief Justice of India on 10th June. 1992. Both the Custodian and the Special Court have started functioning. The Custodian has notified the names of forty persons and institutions under the provisions of the Ordinance in order to prevent the diversion of the property of the offenders.

The Central Bureau of Investigation has so far registered ten regular cases against various individuals and institutions who were found to be involved in offences relating to securities transactions. The investigations of the CBI are continuing. As started by the Finance Minister on the floor of Parliament, all possible action is being taken on priority basis for appropriate penal action against the guilty.

The constitutional validity of the Special Court Ordinance was challenged in the High Court at Bombay. On 24th July, 1992, after hearing the parties, the High Court dismissed the writ petition. The Stock Exchanges had also field petitions before the Special Court in Bombay. After appearance of the Attorney General before the Special Court on 27th July, 1992, the Special Court have issued ruling regarding the effect of the notification issued by the Custodian. The Government have taken into consideration these developments as well as the suggestions received for beneficial improvements in the Ordinance while converting it into an Act. The matter con- also discussed in the Cabinet and certain amendments of clarificatory nature have been proposed. The Finance Minister also had informal discussion of this matter with some of the Oppolition leaders on 7th August, 1992. The Govern-

[Shri Dalbir Singh]

ment share the concern expressed in the House regarding the irregularities in securities transactions and is committed to take prompt action against the offenders and to prevent the recurrence of such irregularities.

This Bill has already been passed by Lok Sabha. I submit that this Bill may be taken into consideration and passed unanimously and expeditiously.

The questions were proposed

3.00 P.M.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujarat): Sir, the previous Bill which we were discussing just now and the present one show—it is just a matter of coincidence and it goes to prove the point—that we are getting far too liberal as fas as Ordinances are concerned and this is the danger point. I am not very sure whether we would like to follow the example of the Government of Bihar in the matter of promulgation of Ordinances—they have hundreds and hundreds of them and it has become a way of life with them and we have strictures from the Supreme Court also—or we want to set an example, not only to Bihar, but also to the rest of the country that we mean business. And, Sir, as far as Ordinances are concerned, we have got to be very very careful and we cannot make it a rule. I have serious objections to taking our privilege, the privilege of the House, away by way of Ordinances. In this connection, I seek your permission to cite a Supreme Court case which again deals with the Government of Bihar and it is the famous case of Mr. Wadhwa *versus* the Government of Bihar. With your permission, I would like to quote that. It says:

> "The power conferred on the Governor..." here the Governor is mentioned; but, in the case under discussion, it is the president—"is well within his right. But the power to issue an Ordinance is in the nature of an emergency power."

Sir, they are talking of emergency powers. It should be noted. Again, it says:

> "The power to promulgate an Ordinance is essentially a power to meet extraordinary situations."

Now, Sir, there are two things which come out of this and this is the observation made by the Supreme Court. One is that the situation has to be extraordinary and the other is that there has to be an emergency. So, the very fact that you have come up with an Ordinance shows that you are conceding the fact that the financial situation or whatever occurred was a state of emergency. It was extraordinary, and you could not have waited for the House to meet and to present the Bill which would in turn become an Act. Now, having confessed that it was an emergency, the next question is who was responsible or who is responsible for this state of emergency.

Again, I would like to quote from the famous Supreme Court judgement in the case of Kuruvilla in 1961 wherein the Reserve Bank of India has been given tremendous powers. Sir, I do not want to take the time of the House by quoting all this. But I would like to come to the question as to who was or who is responsible for this situation which is extraordinary, this state of affains which is termed or implied as an emergency. Who is responsible?

Sir, the honourable Finance Minister has gone on record, has utilized all the platforms, saying that it was a case of system failure. But I would like to draw his attention through you, Sir, to the fact that we have an Act, the Banking Companies Act of 1949, which very clearly defines this policy, the banking policy, The Reserve Bank is supposed to be the watchdog agency and it defines the policy. I do not think there is any ambiguity in it. It says:

> "This policy means..."—I am quoting from the Act—"any policy which is specified from time to time by the Reserve Bank in the interest of the banking system,

in the interest of monetary stability or socio-economic growth having regard to the interests of the depositors, the volume of deposits, other resources, etc. etc."

Sir, the moot point here is the stability of the financial, economic dealings of the country. And who is the watch-dog? Which is the agency? And I must say here, Sir, we are very very proud of that agency, the Reserve Bank of India. Today, we have seen that the Reserve Bank of India itself is found wanting. And again, the Supreme Court judgment I referred to says further to the effect that if the Reserve Bank of India is found wanting, then the only other agency which can intervene is the Central Government through the Ministry of Finance.

So, Sir, my question is: Who is responsible? Who is reponsible for this loot? Sir, here I am on the subject of promulgation of this Ordinance which we are discussing as a Bill. Now, who is responsible for this extra-ordinary situation? There has to be one thief, one person or a set of persons or organisations or associations which are termed as a party to the loot, who have conducted this loot on the nation, which is an anti-national activity. Sir, there has to be always two parties. Which is the other party? Who was responsible to keep a watch? Who was responsible to see that the gates of security are closed and properly locked, and there is somebody watching over? So, there has to be two parties. In the case of the financial systems of the country, enormous powers—I again say at the cost of being repetitive—are conferred on the Reserve Bank of India by Acts of Parliament, etc. The Reserve Bank of India was really the watch-dog agency. There could be two situations, Sir. One is either they were a party to the loot or they were totally negligent in carrying out their constitutional duties and obligations for which they are there by an Act of Parliament. Sir, in both the cases, I repeat, in both the cases, they are a party. In the first case, they are a party because they have connived with the looters. In the second case, they have not done their part of the obligation and duty. May I ask, Sir: What is the provision here? I do not find any provision in this particular Bill which says about not only those who have looted but also those who are responsible for bringing the looters to the door and, perhaps, helping to a certain extent. Now, so many names of people in responsible positions, be it politicans, be it bureaucrats, be it managers or executive, have found their way. Sir, I do not find any kind of provision by which this particular Bill will pinpoint responsibility and accountability.

Sir, now I come to the technical point —which I would want the hon. Minister to respond—as to what was the emergency. We all know as to what has happened. Perhaps, we sitting here would know more. What was the emergency and how are you going to treat both the looters and those people who are responsible for letting in the looters?

Sir, the technical part of the Bill, sub-clause (2) of Clause 2 says: "The Custodian may, on being satisfied on information received that any person has been involved in any offence..." Sir, here, I am referring to the word 'offence'. The word 'offence' has not been clearly defined. What kind of offence, what offence under which Act, are you talking of? I feel that it should have been made more clearer—this is quite ambiguous—that an offence means so and so under such and such Act which also includes such and such. So, there is no scope for any kind of ambiguity which is there at the moment.

Coming back to the point of loot and who was responsible for keeping the doors open, I think, we are getting into a situation where the accused is going to clear his own case and on that parti-

[Shri Dineshbhai Trivedi]

cular case, the rest of the world is going to be debating about. I am coming to the Janakiraman Report itself because we are all deliberating, whether it is the C.B.I., whether it is the Special Court, whether it is the Members of Parliament in both the Houses, or perhaps the JPC itself, and they are going to depend totally on the Janakiraman Report itself. My objection here is as to why we include an agency which itself is a suspect in the public eye. I am coming to the Public Debt Office which was a part and parcel of the scam. The sequence which has taken place, to the best of my knowledge is like this. Because the SGL account comes under the Public Debt Office which is a part of the Reserve Bank of India's office, the sequence of events which I have here is that when the statement, that is, the SGL, was received by the Fund Management Department from Bombay's main branch on 6-4-92, there were some discrepancies and over-writings on it. The SGL is coming from the Reserve Bank of India's Public Debt Office and it goes to the Fund Management Department, or the FMD. Here, Sir, I have to be a little technical to prove my point. An officer from the FMD was sent to the Public Debt Office. It is in a reverse order. An officer from the FMD was sent to the Public Debt Office of the RBI to reconcile the statement of that branch with the Public Debt Office, and that is where they found that there was some kind of a correction in RBI's PDO. It was found that in case of 11.5 per cent, the figure of 2010 was shown and the figure of Rs. 1670.95 crore was altered cleverly by someone before sending the statement to FMD. The point I am trying to make is that the Public Debt Office was very much a part and parcel of this scam getting aggravated. The scam would never have reached this proportion had the Public Debt Office been vigilant, and the hon. Finance Minister himself—not really referring to PDO — has gone on record saying that the RBI should have definitely been more vigilant. Now this term 'more vigilant' is a relative term. What I am trying to say is that there is no provision in this Act...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Your time is already over. Therefore please conclude in one or two minutes

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: I will conclude in two minutes. In conclusion, I would like to say that the Act has no scope to deal with these matters I am sure, I have no doubt, and I always pay compliments to the hon. Finance Minister that he has got such a good track record as far as his honesty is concerned. While a lot of things are getting unearthed, I do not know whether he has some other political compulsions because of which the agencies are not allowed to function freely. I do not know if there are any political constraints. It has always happened with honest people that they may want to go ten steps forward but because of political compulsions, instead of taking a step forward, they go a step beckward. We hold the Reserve Bank of India in very high esteem and in order to enhance its prestige, there is no reason why we should try and protect individuals. The inquiry is still going on, the CBI is still at its work, but I don't know how the hon. Finance Minister has given a clean chit to the Governor of the RBI. I really don't know why. Is it not true that by giving such clean chits you are sending a message—in this country political messages are there—intentionally or otherwise, not to touch the Governor or the RBI at all because they are above board? What is the basis? It means the hon. Finance Minister would know much more than the CBI and if he does, then we would like to know what the further details are.

Lastly, Sir, the scam—because of the scam we have the special courts and that's why I am referring to it—could never have had such proportions had the bureaucrats, politicians, people in public service, people who are supposed to be the custodians of the faith—I am not talking only in terms of money but the faith—the people of this country had put in them, have not only neglected their duty, but at places there has been

connivance also. We have the case of a Padma Vibhushan, Mr. Krishnamurthy. Can you imagine it? This is the first time that a man with a Padma Vibhushan is in jail — and what are the charges? The charges are anti-national activities—that he was trying to destabilize the economy itself. The point I am trying to prove is, there is no provision by which you are going to set an example so that in future these things do not occur. So I would humbly plea with the hon. Finance Minister whether he would like to incorporate some such clause by which two things may happen: (1) You still give a chance to an independent body, besides the Janakiraman Committee, to investigate further. There is nothing wrong. At times we take consultation from two doctors, three doctors, so that, may be, there is a cross-check of the system. Would he consider including that? Would he also consider some kind of a clause in this Bill whereby you pinpoint responsibility ...

श्री चतुरानन मिश्र : पदम विभूषण का क्या हुआ। वे वापस करेंगे ?

श्री विनेश भाई त्रिवेदी : वही हम पूछ रहे हैं कि अब यह पदम विभूषण जो दिया गया है.....

श्री चतुरानन मिश्र : वह देने का ही कानून में कि वापस भी लेने का ?

श्री विनेश भाई त्रिवेदी : वही हम पूछना चाहते है कि यह हमने दिया

That is a black spot. When you talk of it, it is unfair on other recipients of Padma Vibhushan. It is just a very, very rare case, and I have no doubt that the others who are there well deserve it. But it is a black spot. So I would like to ask the Government what they are going to do about it. Is there any provision? I know that he has not yet been on that, but is there any provision by which you can recall this? ...(*Interruptions*)... I think it shows that we have to be very, very careful in giving these decorative awards.

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): Let us stop it at least for 25 years.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Like the Games, is it? Like Barcelona we had discussed, that we don't send people for Games? Like that we will stop this also. ...(*Interruptions*)...

Sir, the rate at which people are getting bought over—and it has an approval also—I think it has come to a very dangerous proportion. Sir, I am very sad today that the reputation of the entire country is something which it doesn't deserve because I am still confident that the majority of the people of this country, specially the poor, are very honest, very humble and very law-abiding. It is just because of a very small fraction of the people of this society, namely, the people who are sitting at Gangotri. And we are the people—the politicians, the bureaucrats—who are sitting on top from where the Ganga is flowing, and we are the people who are part and parcel, in some way or the other. May be that percentage is small, but that small percentage is good enough to create a big virus and really take the health of this nation for a ride. So, I would plea with the Government not to give an impression — you know Madhavan has resigned and all that — that you would like to cover up more which may not be your intention, but I must tell you that that is the signal going that you would like to segregate those whom you want to punish from those whom you do not want to punish. There is the question of Fairgrowth and the question of Chaturvedis and all those people involved in it.

In conclusion, I would plead: please let this be totally transparent. Please ask the public. Hear everybody. Don't close your mind. And least of all, don't start giving clean chits to anybody.

I support the Bill, all right.

Thank you, Sir.

SHRI MADAN BHATIA (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill, and I wish to congra-

[Shri Madan Bhatia]

tulate the Government for having brought before this hon. House this particular Bill in furtherence of its repeatedly declared determination that any person who has been involved in this gigantic fraud, by which some people dealing with public money, public securities, enriched themselves and at the same time created tremendous misery for a large number of common men, must be brought to book speedily and must be punished with exemplary punishments. This particular point has been missed by the hon. Member who has preceded me.

The hon. Member has not correctly appreciated the scope of this Bill. The scope of this Bill is a very limited scope. It has two facets: One is that a machinery should be established for speedy and expeditious trial of such offenders as are found to have committed or as are found to have been a party to this gigantic fraud which has been played on the country. This is one facet.

The second facet of this Bill is that the properties of such persons must be immediately attached during the course of the trial because you cannot seize the properties and dispose of the properties unless they are convicted. What can you do? You can attach the properties so that it should be safeguarded and should be made available if those persons are convicted.

For what purpose? The purpose is given in clause 11. It says that the following liabilities shall be paid:

> "(a) all revenues, taxes, cesses and rates due from the persons notified by the Custodian under sub-section (2) of section 3...."

It means persons who are involved in these offences.

> " to the Central Government or any State Government or any local authority;"

If those persons are convicted, their properties, whether moveable or immoveable, must be made available for payment of all the taxes which may be due from such persons to the Central Government, any State Government or any local authority.

Secondly, it says:

> "(b) all amounts due from the person so notified by the Custodian to any bank or financial institution or mutual fund;"

If they have committed a fraud, as a result of which a bank has been deprived of its moneys, their properties, moveable or immoveable, shall become available, on their conviction for payment of the moneys due to the bank.

Thirdly, it says:

> "(c) any other liability as may be specified by thee Special Court from time to time."

This is a very general and a very wide power which has been conferred upon the Special Court. It may be that a person has committed a big fraud and has been convicted and nothing may be due from him to the Central Government by way of taxes, nothing may be due from him to the banks but still that money has gone into his pocket as a result of that fraud which he has committed in relation to the transactions concerning the securities and he has been convicted by the special court. Then, the special court will have the power to see that he is dispossessed of that money and the liability which he owes to any other person is also met. These are the limited objectives of this particular Bill.

The hon. Member has said a lot that there are so many persons who are responsible and this Bill makes no mention of that. I submit, Sir, that it is not open to him to forestall the proceedings or the report of the Joint Parliamentary Committee. If the Joint Parliamentary Committee has been established, it has been established *inter alia* precisely for this purpose to find out as to who is responsible for this fraud or scam. The Joint Parliamentary Committee has been established

under the fiat given by the Parliament. We are all party to the constitution of the Joint Parliamentary Committee. It is for the Joint Parliamentary Committee to decide and to find out as to who is responsible, any bank official, any bureaucrat, any politician, and citizen of this country, whether he is residing within the country or outside the country. I have full faith in all the Members of the Joint Parliamentary Committee. I have no doubt that the Joint Parliamentary Committee will expose to the hilt any person who is responsible for having committed this fraud. Therefore, I will appeal to the hon. Member to desist from forestalling the report of the hon. Joint Parliamentary Committee and levelling allegation with regard to the responsibilities of the various individuals in a very vague, general and in such Wild language.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: For the clarification of the Member, I think it is very unfair to overread or have his own interpretation to what I had said. We are restricting it to the Bill. The JPC has been formed or for that matter the CBI was investigating into the matter because of the Opposition's demand. I know very well that the Opposition had not demanded this vociferously, things would not have happened in this way.

SHRI MADAN BHATIA: Sir, if you read the opening part of the speech of the hon. Member, that speech is nothing but throwing around vague, wild and general allegations of responsibility on Humpty, Dumpty and all and sundry. I respectifully submit that this honourable House had heard the speech of the hon. Member. I have heard his speech with rapt attention. I stand by what I have said that it was not open to the hon. Member to forestall the report of the Joint Parliamentary Committee which will go into the very question of the responsibility of the various individuals.

Secondly, Sir, the hon. Member has said that this Bill deals only with the offenders. This Bill makes no mention about the punishment of the persons who may have not committed any offence but who are responsible. This is a remarkable elucidation or exposition of criminal jurisprudence. Neither under the Constitutional law not under the criminal jurisprudence one can create an offence with retorspective effect. Even the Parliament does not have this power. Either a person has committed an offence which already exists on the statute-book or he has not. Parliament cannot sit down and say that... What he did in 1991, we declare that it shall be thus treated as an offence. This power, the Parliament does not have. If any person has not committed an offence, then, he has not committed an offence. If he happens to be a member of the bureaucracy, he can be proceeded against according to the rules of service. If he happens to be a politician, he will have to pay the price at the bar of the people. But if he has been a party to the commission of a fraud by another individual, then, he will be equally guilty of an offence under section 120 (B) of the Indian Penal Code as a co-conspirator. But if you cannot bring him under section 120 (B) of the Indian Penal Code, then, you cannot say, you cannot even make a law to say, that he was responsible, although he had not committed an offence. Therefore, he must still be punished and for that an offence may be created by another Bill to be brought before the Parliament. So this Bill possibily could not contain any provision dealing with persons who have not committed any offence but who may just be responsible. For that the remedy is elsewhere with the Government so far as the bureaucracy is concerned, with the people of India and the Parliament for political indictment so far as any politician is concerned.

Now, Sir, I submit that the third point which has been made by one hon. Member on this side is that the Special Court will follow a procedure which is not clear. Clause 9 of this Bill makes it absolutely clear that the procedure which is to be followed by the Special Court will be the procedure as prescribed

[Shri Madan Bhatia]

by the Criminal Procedure Code. This invariable has been the provision in the various statutes which created special courts for trial of various offences. I will just give one example. In 1978 the Special Court Bill was brought forth for trial of offences committed by persons holding high political authority by special courts and this was exactly the provision which was contained in that Special Court Bill. The procedure has to be prescribed and the procedure which has been prescribed is the procedure as drafted in the Criminal Procedure Code and that was the procedure which was prescribed in the Special Court Bill which was brought before the Parliament by the then Janata Party Government for trial if persons holding high political authority the object of which was... (*Interruptions*)...I am not saying Janata Dal. I am saying the then Janata Party. This was exactly the procedure prescribed in that Bill. The then Janata Party Government included, at that time, those who today are members of the Bharatiya Janata Party and the hon. Member belonging to that party has stood up to criticise the procedure prescribed in this Bill. Sir, these are the points which have been made by the hon. Members on this side and to the best of my ability, I have tried to meet them.

I would now like to say that this Bill has been brought under a big handicap. We know that a big fraud has been committed. Some of the names have also stood exposed. But we do not know really as to what is exactly the nature of offences which have been committed. We are not very clear. This will become clear after the report of the Joint Parliamentary Committee... or after the investigations are completed by the CBI. The shadow of this handicap can be seen in the manner in which sub-claus 2 of clause 3 has been drafted. It says:

> "The Custodian may on being satisfied on information received that any person has been involved in any offence relating to transactions in securities..."

It may be said that the expression "any offence relating to any transaction" is very wide. The Supreme Court says that when you constitute a special court, the types of offences and the types of offenders should be categorised; otherwise, it may suffer from the infirmity of vagueness. At the moment, it was not possible for the Government to specify the types of offences which would be covered by this particular statute. The Government was left with no choice but to use the general expression "any offence relating to transactions in securities". I am saying so because this Bill may come under a constitutional challenge and it may be said that the nature of offences has not been categorised and therefore, it suffers from vagueness. The only answer that I can think of on behalf of this particular Bill which has been brought forth by the Government is that at this particular stage, it is not possible to categorise the offences except to say that the information that has come is that within a particular period a lot of offences had been committed in relation to securities and the securities have been defined. This is the only answer that could possibly be given and that may go home in the minds of the judicial authorities.

Secondly, Sir, sub-clause 2 of clause 3 further says.

> "...after the 1st day of April, 1991 and on and before the 6th June, 1992, notify the name of such person in the Official Gazette."

We know why the particular date, 6th June, 1992, has been chosen because that was the deadline when the whole thing was brought to a stop by the immediate intervention of the Government after the revelation of this big fraud. But the question that arises is, what is the basis for having chosen the particular date, 1st day of April, 1992? Why have they limited these offences to the 1st day of April, 1991? (*Interruptions*).

SHRI CHATURANAN MISHRA: Because that is the fools' day.

SHRI MADAN BHATIA: I hope you are not referring to me.

Or, it may be said conversely, why have you picked up 1st April, 1991, why have you gone so far as 1st April, 1991? I am raising this point because this point arose on the Special Courts Bill, 1978 before the Supreme Court when the President referred that particular Bill for opinion to the Supreme Court as to its constitutional validity. That Bill provided that any offence which was committed by a person holding a high political office or a high political authority from the 25th February up to the end of emergency would be covered by that particular Bill. The Supreme Court said, "There is no rationale behind the choice of 25th of February 1975. The emergency was declared on 26th of June 1975." The Supreme Court said that the Special Courts Bill was not valid in so far as it provided for trial of offences from 25th of February to 26th of June 1975 because they were pre-emergency offences. They were not connected with emergency and the whole objective behind this particular Bill was to try persons holding high political authority for offences which were committed during the emergency. The allegation was that they misused the powers conferred by the emergency. So that part of the Special Courts Bill was struck down--25th of February to 26th of June 1975.

This Bill also does not contain the aims and objects and I am at a loss to understand this. I have been told that this date has been selected because there is a reference to this date in Janakiraman's report. But what is the logic behind the choice of this particular date? I would request the hon. Minister to enlighten this House, this is one point.

Thirdly, Sir, there is one other infirmity from which this particular Bill, to my mind, suffers. According to the judgment or according to the opinion which was given by the Supreme Court in regard to the Special Courts Bill in 1978, there is no provision in this Bill for transfer of a case from one special court to another special court. Supposing, the presiding judge of a particular special court becomes biased and the accusd finds that he is not going to get justice from this particular judge presiding over this particular special court, then he must have the right for transfer of that case to another special court. This is what the Supreme Court said. I would like to read this particular paragraph before the hon. Members. This is from the opinion of the Supreme Court reported in AIR 1979 Supreme Court. The judgement is a very long judgement. I am reading from page 517 Supreme Court says:

> "Though this is so the provisions of the Bill appear to us unfair and unjust in three important respects. In the first place, there is no provision in the Bill for the transfer of cases from one special court to another. The manner in which a judge conducts himself may disclose a bias in which case the interest of justice would require that the trial of the case ought to be withdrawn from him. There are other cases in which a judge may not, in fact, be biased and yet the accused may entertain a reasonable apprehension on account of attendant circumstances that he will not a fair trial. It is of the utmost important that justice must not only be done but must seem to be done. To compel an accused to submit to the jurisdiction of a court which, in fact, is biased or, is reasonably apprehended to be biased, is a violation of the fundamental principles of natural justice and a denial of fair play. There are yet other cases in which expediency or convenience may require the transfer of a case even if no bias is involved. The absence of provisions for transfer of trial in appropriate cases may undermine

[Shri Madan Bhatia]

the very confidence of the people in special courts, as an institution, set up for dispensing justice..."

Then the Lordship gave this opinion: "These, in our opinion, are the three procedural infirmities." The other two procedural infirmities I need not dwell upon because they have been taken care of in this particular Bill, but I am speaking on this particular infirmity. "These, in our opinion, are the procedural infirmities from which the Bill suffers and which are violative of article 21 of the Constitution in the sense that they made the procedure prescribed by the Bill unjust and unfair to the accused."

Sir, a very famous American Judge once observed and his observation has been adopted by the Supreme Court in some judgments-and that is, "The history of liberty is a history of strict observance of procedural safeguards." The whole nation may be very much agitated and rightly so, about this gigantic fraud which has been unearthed, but the procedural safeguards have been provided by the founding fathers of the Constitution in article 21 of the Constitution. And it is by relying upon these procedural safeguards, contained in article 21, that the Supreme Court held that by the absence of a provision for transfer of a case from one special court to another special court the Bill suffers from a constitutional infirmity. So this point may arise if this Bill comes up for a challenge before the hon. Supreme Court.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Do you mean to say that section 526 of the Cr. PC may not apply for transferring a case from one court to another?... (*Interruptions*)...

SHRI MADAN BHATIA: There is only one special court and there is no provision for giving a right to an accused to make an application for transfer of a case from one special court to another special court. So I am only seeking to alert this hon. House, lest this Bill should get entangled in constitutional and legal wrangles before the court which will defeat the very purpose of this particular Bill.

श्री चतुरानन मिश्र : इसमें "दन कोर्ट" की जगह "मोर कोर्ट" कर दिया जाए तो will it suffice?

SHRI MADAN BHATIA: No; there has to be a specific provision for conferring the right upon the accused to make an application to a particular authority for transfer of the case...

SHRI DAYANAND SAHAY (Bihar): The number of judges can be increased.

SHRI CHATURANAN MISHRA: No, no; that will not serve the purpose. If the court is one, the number is one, that will not serve the purpose. What you are saying is a very valid point. If you establish more than one court then can it be done?

SHRI MADAN BHATIA: No, then it cannot be done. Suppose, there is a case pending in the Punjab High Court, a criminal case, that has to be transferred. Then there is a provision contained in the Code of Criminal Procedure, giving power to the accused to move to the Supreme Court for transfer of the case. There has to be a forum before which the accused can go. He cannot move the application before the same court and say, "Transfer my case."

SHRI CHATURANAN MISHRA: No, no; the Supreme Court is always there. That is why I am saying...

SHRI MADAN BHATIA: But there is no provision saying that the Supreme Court shall have the power to transfer... (*Interruptions*)...

SHRI CHATURANAN MISHRA: Supreme Court has the supreme power.... (*Interruptions*)...

SHRI MADAN BHATIA: This is a specific point. It can't be treated as an inherent power. If that were so, even this Special Court Bill provided for an appeal to the Supreme Court...

SHRI CHATURANAN MISHRA: The fact was that another court was not there.

SHRI MADAN BHATIA: It is not just that there is no other court. Even if there is another court, there has to be a procedure for transfer of the case. There is no procedure prescribed for transfer of the case. There is no forum prescribed before which that procedure is to be followed by the accused for transfer of the case. Both things have to be there. There has to be more than one special court and there has to be a procedure for transfer of the case. This is my submission. With regard to this particular Bill, I submit that the objective of this Bill is laudatory and I whole-heartedly support this Bill, notwithstanding some misgivings to which I have given my expression. Notwithstanding the misgivings, it is my duty, as a lawyer, to point out what difficulties may arise.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): You are not only a lawyer but also a Member of this House.

SHRI MADAN BHATIA: I am too humble a Member to have a prerogative of enlightening the hon. Members of this august House. I would like to say at the end, and I had said earlier also, that we have a Joint Parliamentary Committee which is going in detail into all these matters and one of the terms of reference has specifically provided to fix the responsibility of persons who are involved in this scam. So, they have to find out the offences and the responsibility. The terms are wide enough to cover the discovery of offences and the discovery of offenders. Difficulty may arise there. I said so on 9th August and I want to repeat now because special courts are being established and the object of the special court is to hasten the trials. If FIRs have been lodged and after that a challan is filed in a special court, much more serious questions will arise. The person against whom the challan is filed before the special court becomes not only a potential accused as in the case of an FIR but a full-fledged accused. Then he has all the rights open to him to defend himself as provided under the Constitution. One of the rights is to remain silent. This question may assume importance if a persons against whom a challan is filed in the court is summoned by the Joint Parliamentary Committee for interrogation. And he refuses to depose, what will be the stand of the Joint Parliamentary Committee? The only action that the Joint Parliamentary Committee can take is that you have committed a breach of privilege and proceed against him for commission of a breach of privilege. And what can the accused say? On this also I will share my views with the hon. Members. The Supreme Court in 1965 Reference Case held that where the Constitution says that the Parliament shall be the sole authority to control its own procedure and proceedings, that provision in the Constitution does not override the fundamental rights of a citizen. The Supreme Court went to the length of holding that if an illegal warrant is issued by the Legislature against any person which violates his fundamental rights, he has a right to come to the court and say that his fundamental rights have been infringed and this warrant which has been issued is illegal. There was one case in 1950's which arose from Bombay Legislature. On the warrant issued by the Speaker of the State Legislature for breach of privilege he was arrested; but he was not produced before the Magistrate within a period of 24 hours as prescribed by the Constitution. He challenged the validity of his warrant and his continued detention. The matter went to the Supreme Court. The Supreme Court held that because he was not produced within a period of 24 hours before the Magistrate, this violated his constitutional rights and his continued detention was illegal and he was set free. So, these question will arise. These question may arise even at the stage of FIR because the Supreme Court says that when an FIR is lodged against an individual he cannot be an accused but he is a potential accused. He is entitled to the presence of a counsel at the time o this interrogation under Articles 20 and 21 of the Constitution. At the same time he may refuse to answer those questions which will directly incriminate him. He can pick and choose. This is the Satpathi case of 1978. Supposing a person is summoned by the Joint

[Shri Madan Bhatta]

Parliamentary Committee against whom FIR has been lodged and he is sought to be interrogated and he insists, "I would like my counsel to be present". What would be the position then? Supposing he says, I will not answer this particular question because answer to this question is going to be incriminatory. What will be the stand of the Joint Parliamentary Committee? These are very important Constitutional questions. (*Interruptions*). I am coming to that. That is my separate point. Sir, apart from this, supposing a trial starts before the Special Court and at the same time investigation against him starts before the Joint Parliamentary Committee. Supposing he comes forward and says, "I cannot be a victim of a double jeopardy, there cannot be a double investigation or a double trial against me. It should be either before the Special Court or before the Joint Parliamentary Committee, not before both". What would be the position? As the hon. Member has said, he may say, "My trial is likely to be prejudiced before the Special Court by your simultaneous investigation and inquiry against me." Then he may say that Article 21 of the Constitution says, "No person shall be deprived of his liberty except in accordance with the procedure established by law." Supposing he comes forward and says that this Joint Parliamentary Committee has been established not by any law but by merely a resolution of Parliament. Resolution is not a law. Even an inquiry and an investigation is part of the procedure which must be established by law because this is what the Supreme Court says. The procedure which ultimately may lead to the deprivation of liberty has to be established by law and the Joint Parliamentary Committee is not established by law. He may question the very jurisdiction or authority of the Joint Parliamentary Committee to hold this inquiry. I am just posing these questions before the hon. Members. I am giving no answer. I am posing these questions before the hon. Members in the hope that the hon. Members will ponder over them. Not that we can do anything, but it is our duty that we should know what may come ahead of us. We should be ready for argument. That is all, Sir. I thank you and once again congratulate the Government and support this Bill.

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष जी, हमारे दूसरे साथियों ने ही शब्द उधार लेकर मैं कह सकता हूं कि जाइजेंटिक फ्रोड है उसके बारे में यह विधेयक लाया गया है स्पेशल कोर्ट के लिए। यह कोर्ट, इसका विचार और दोषी को दंडित करने के लिए दूसरे मकसद से बनाये गये हैं। वह हम तब कर रहे हैं जब हमारा एरेन्जमेंट जो था, जो सिस्टम था आर०बी०आई० के तहत वह सही ढंग से ऐसे घोटाले को रोकने में नाकामयाब हुआ और जब उसकी गंध मिली एक साल के बाद कि आर०बी० आई० के जो डिपार्टमेंट वगैरह हैं उनको जिन चीजों को करना चाहिए था— वह

4.00 p.m. फेल हुआ, विफल रहा या नहीं, मैं इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि इस विधेयक का जो मकसद है यह उसके तहत नहीं है। इसके बारे में जे०पी०सी० बनाई गई है। यहां सदन में भी कई बार इस बारे में बात हो चुकी है लेकिन मंत्री जी स्वीकारते नहीं हैं आर०बी० आई० की जिम्मेदारी, जबकि सदस्यों का यह कहना है कि आर० बी० आई० भी जिम्मेदार है। इस विधेयक के मकसद में कहा गया है कि आर० बी० आई० को घोटाले का जब पता चले, उसके तहत यह स्पेशल कोर्ट काम करेगा जब कि उनकी जो जिम्मेदारी है, आर०बी०आई० की, उसके विचार के लिये, उसमें जो दोषी हैं उनके बारे में इसके उद्देश्यों में बात नहीं कही गयी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे एक के बाद एक तथ्य हमारे सामने उजागर हो चुके हैं, पहले मामूली कुछ कर्मचारियों और कुछ दलालों का व्यापार था, इस तरह से कहकर इसको टालने की कोशिश की गयी। लेकिन अब वह बात नहीं रही। यह जाइजेंटिक फ्राड है, जिसमें एक से एक आला अफसर और बैंक के एक्जीक्यूटि और उनके साथ साथ जो पोलिटिकल हाई-अप्स हैं, राजनीति करने वाले लोग और ब्यूरोक्रेट्स, एक दम

ऊंची जगहों पर जो बैठे हुए लोग हैं, वे भी किसी न किसी तरह से इसके साथ जुड़े हुए हैं और यह मामला हम सब के सामने आ गया है। जो यह कहा जा रहा था कि यह सिस्टम फेल्योर है, यह ही नहीं बल्कि सिस्टम के पीछे जो लोग हैं यह उनका फेल्योर रहा है, इसलिये स्पेशल कोर्ट के तहत हम इसके शीघ्र निपटारे की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारा यह सवाल है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी, जो इस घोटाले से जुड़ा हुआ है, उनको कहीं भी छूट नहीं दी जायेगी, तो यह आनेस्टी का सवाल है, ईमानदारी का सवाल है। हम यह चाहते हैं कि स्पेशल कोर्ट, जो अध्यादेश के द्वारा बना है, वहां जब विचार किया जा रहा है तो एफ०आई० आर० में जिनका नाम है, ऐसे व्यक्तियों के विरोध में जो केस धर नहीं किया गया है, या उनकी जो सम्पत्ति है उसको कुर्क करने के लिये, जिस उद्देश्य के लिये यह स्पेशल कोर्ट बना है, वह नहीं किया गया। जिनका नाम एफ०आई०आर० में दर्ज है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। जिनका नाम एफ०आई०आर० में दर्ज नहीं है उनकी बात अगर छोड़ भी दें, ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन जिनका नाम एफ आई० आर० में आ रहा है, तो हमें यह चाहये कि जिनका नाम एफ०आई०आर० में दर्ज हो तो अगर हम वसूल करना चाहें और शीघ्र वसूल करना चाहें तो हमें उनको यह मौका नहीं देना चाहिये कि उनकी प्रापर्टी जो है वह डाइवर्ट हो जाय। हमें जल्दी से जल्दी उनके विरोध में कार्यवाही करनी चाहिये वरना हम जो पुनः विश्वास स्थापित करने जा रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय संस्थाओं के ऊपर, वह नहीं रहेगा, हमें पिछले दिनों का यह अनुभव है। मूंदड़ा केस के बारे में मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हम कितनी प्रापर्टी अटेच कर पाये हैं और कितनी कर पायेंगे ? जो हजारों करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है उसके अंदर कितने रुपये हम कुर्क की गयी प्रापर्टी के जरिये वापस ले पायेंगे ? अभी हमारे दूसरे वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि सिर्फ कुर्की कर देने से ही वह पैसा वापस आने वाला नहीं है क्योंकि इसको कानूनी रुख देकर कोर्ट में काउंटर लिटिगेशन करके इसको फंसाने की कोशिश की जायेगी। तो इससे निपटने के लिये आप क्या गार्ड रख रहे हैं ताकि यह कोर्ट के चक्कर में न फंस जाय। साथ ही जो स्माल इनवेस्टर थे, जो डिपाजिटर्स हैं, जिनको शेयर मार्केट का लालच दिखाकर जिनसे रुपया खींचकर लाया गया, उनका पैसा वापस करने के लिए आप क्या प्रबंध करेंगे ?

दूसरा सवाल यह है कि जो लोग इसमें हैं उनकी कितनी प्रापर्टी अटैच की गयी है और उनकी रकम क्या है ? जो पैसा नहीं दिया गया है उसको शीघ्र निपटाने के लिये, कोर्ट बनने के बाद, अध्यादेश बनने के बाद और जब यह विधेयक पास करेंगे तो हम इसको कितना जल्दी कर पायेंगे क्योंकि हम यह देख रहे हैं कि हमारे यहां हर्षद मेहता वगैरह, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही की गयी। कार्यवाही की गयी ठीक है और करनी चाहिये। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पकड़ा नहीं गया। एफ०आई० आर० में नाम भी है फिर भी छोड़ दिया गया। उनके विरुद्ध केस शुरु नहीं किया गया। यह लोग बाहर रह कर दस्तावेजों को और कागजात को नष्ट कर रहे हैं। जो प्रोपर्टीज, एसेट्स और पैसा है उसको फिर से डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को विदेश जाने का मौका भी मिला है। ऐसे लोग देश में रह कर अब भी उस पैसे को रीचेनालाइज कर देते हैं। उस को छिपा रहे हैं, दूसरी जगह हटा रहे हैं। इसके बारे में आप कौन से गार्ड लेने का प्रबन्ध कर रहे हैं ताकि इसको रोका जा सके ? इसके इलावा यहां पर सरकार की सच्चाई और ईमानदारी का भी सवाल आता है। हमने उद्देश्य में यह कहा है कि वसूली शीघ्र सुनिश्चित कर लेंगे लेकिन हम यह देखते हैं कि जब हमारे सामने एफ०एफ० एस०एल० या मी०एफ०सी० का सवाल आता है और जब आप सी०बी०आई० के द्वारा

[श्री मोहम्मद सलीम]

जांच करवा रहे हैं कुछ नीयत का सवाल उसमें आ जाता है, सी०बी०आई०, के अफसर के उस विवाद को मैं यहां नहीं छेड़ना चाहता हूं । लेकिन सरकार इसको स्पष्ट करे कि ऐसा कोई विवाद उत्पन्न न होने दे तो बेहतर होगा । हमने बोफोर्स के सवाल पर देखा है कि किस तरह से सच्चाई को कवर-अप करने के लिए कोशिश की गई । उसी तरह से यहां भी डर उत्पन्न होता है । हालांकि जे०पी०सी० भी है वह अपना काम कर रही है लेकिन अब तक जो कार्यवाही की गई है उसमें ऐसे कुछ सवाल पैदा हुए हैं जिसमें सरकार की नीयत के बारे में जनता के अन्दर कुछ प्रश्न चिन्ह लगा है मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार इसे स्पष्ट करे और वाकई इसके पीछे जो राजनीतिज्ञ या ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए हैं, अब भी बहुत से लोगों का नाम आ रहा है इसलिए सरकार को चाहिए कि वह सिलेक्टेव एप्रोच अख्तियार न करे बल्कि सच्चाई के साथ जिनका भी नाम आए उसको स्पष्ट किया जाए । जैसे वह कहते हैं, करके भी दिखाएं । जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये स्पेशल कोर्ट के जज ने खुद कोर्ट में यह कहा है कि यहां पर कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे लगता है कि जो लोग जुड़े हुए हैं सब के विरुद्ध कार्यवाही शुरु करने के बजाए कुछ स्केपगोट खोजा जा रहा है, बलि का बकरा खोजा जा रहा है, उसको सामने लाया जा रहा है और बाकी लोगों को छूट दिलाने की कोशिश की जा रही है । यह मेरा कहना नहीं है, स्पेशल कोर्ट के जज ने कहा है । इससे जनता के बीच में जो भावना पैदा होती है उससे सरकार की नीयत के बारे में प्रश्न चिन्ह लग जाता है । मैं इसी के साथ यह कहना चाहूंगा कि बिल के क्लाज-3, सेक्शन-2 में यह कहा गया है कि जो सिक्युरिटी ट्रांजेक्शंस हुई हैं उसके दौरान जो एवीडेंस पता चलेगा वह फर्स्ट डे आफ एप्रिल, 1991 एंड आन और बिफोर सिक्स्थ जून, 1992, यह फर्स्ट एप्रिल का महत्व क्या है ? उससे पहले क्यों नहीं ? जैसे कि सदन में भी बातचीत हुई और बाहर पत्रिकाओं में भी आया है कि यह प्रतिभूति घोटाला तो इससे पहले भी शुरु हो चुका था । रिज़र्व बैंक के पुराने अफसरों का कहना है कि खुद रिज़र्व बैंक को इस बारे में मार्च, 1991 में पता चला था । तो उससे पहले फर्स्ट अप्रैल से पहले जो ट्रांज़ेक्शन हुआ उसके बारे में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसके तहत हम क्या कार्यवाही करेंगे ? स्पेशल कोर्ट को आपने फर्स्ट अप्रैल के बाद की जिम्मेदारी दी है लेकिन मैं मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इस डेट का क्या महत्व है और उसको पहली अप्रैल ही क्यों रखा गया है ? इतना कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

†[ ] Transleteration

†[شری محمد سلیم] مغربی بنگال : آپ سبھا
ادھیکش جی۔ ہمارے دوسرے ساتھیوں سے
بھی شبد ادھار لے کر میں کہہ سکتا ہوں کہ
جو جانکاری فراڈ ہے اس کے بارے
میں یہ ودھیک لایا گیا ہے اسپیشل کورٹ
کے لئے۔ یہ کورٹ اس کا وچار اور دوشی
کو نکالنے کے لئے اور دوسرے مقصد اس کے
یہاں کیے گئے ہیں۔ وہ ہم تب کر رہے ہیں
جب ہمارا ایکجمنٹ جو تھا جو سسٹم تھا
آر۔ بی۔ آئی کے تحت وہ صحیح ڈھنگ سے
ایسے گھوٹالے کو روکنے میں ناکامیاب
ہوا اور جب اس کی گندھ ملی ایک سال
کے بعد کہ آر۔ بی۔ آئی کے جو ڈپارٹمنٹ
وغیرہ ہیں ان کو جن چیزوں کو کرنا چاہیے
تھا.... وہ فیل ہوا۔ پھیل رہا یا کیا
نہیں۔ میں اس پر نہیں جاؤں گا کیونکہ
اس ودھیک کا جو مقصد ہے یہ اس کے

تحت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جے۔ پی۔ سی۔ بنائی گئی ہے۔ یہاں سدن میں بھی کئی بار اس بارے میں بات ہو چکی ہے۔ لیکن منتری جی سویکار کرتے نہیں ہیں۔ آر۔ بی۔ آئی کی ذمہ داری۔ جبکہ سدسیوں کا یہ کہنا ہے کہ آر۔ بی۔ آئی بھی ذمہ دار ہے۔ اس دودھیک کے تحت اور آدیشیوں میں کہا گیا ہے کہ آر۔ بی۔ آئی کو گھوٹالے کا جب پتہ چلے۔ اس کے تحت یہ اسپیشل کورٹ کام کرے گا جبکہ ان کی جو ذمہ داری ہے۔ آر۔ بی۔ آئی کی اس کے وچار کے لئے اس میں جو دفعات ہیں ان کے بارے میں اس کے آدیشیوں میں بات نہیں کہی گئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک کے بعد ایک گھوٹالے ہمارے سامنے اجاگر ہو چکے ہیں۔ پہلے معمولی کچھ کرمچاریوں اور کچھ دلالوں کا ویاپار تھا اس طرح سے کہہ کر اس کو ٹالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن اب وہ بات نہیں رہی۔ یہ جو انٹرک فراڈ ہے جس میں ایک اعلیٰ افسر اور بنک کے ایگزیکٹو اور ان کے ساتھ ساتھ جو پالیٹیکل ہائی اپس ہیں۔ راج نیتی کرنے والے لوگ اور بیوروکریٹس ایک دم اونچی جگہوں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ بھی کسی طرح سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ معاملہ ہم سب کے سامنے آ گیا ہے۔ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ سسٹم فیلیور ہے یہ ہی نہیں بلکہ سسٹم کے پیچھے جو لوگ ہیں یہ ان کا فیلیور رہا ہے۔ اس لئے اسپیشل کورٹ کے تحت ہم اس کے شیگھر نپٹارے کی مانگ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ سوال ہے جو پردھان منتری جی کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو اس گھوٹالے سے جڑا ہوا ان کو کہیں بھی چھوٹ نہیں دی جائے گی تو یہ اتھنٹی کا سوال ہے۔ ایمانداری کا سوال ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسپیشل کورٹ کو اختیارات کے ذریعے بنایا ہے۔ وہاں جب وچار کیا جا رہا ہے تو ایف۔ آئی۔ آر میں جن کا نام ہے۔ ایسے دکھتیوں کے دودھ میں بھی کیس درج نہیں کیا گیا ہے یا ان کی جو سہیتی ہے اس کو تفریق کرنے کے لئے جس اد یشے کے لئے یہ اسپیشل کورٹ بنا ہے وہ نہیں کیا گیا۔ جن کا نام ایف آئی آر میں درج ہے۔ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا جن کا نام ایف۔ آئی۔ آر میں درج نہیں ہے۔ ان کی بات اگر چھوڑ بھی دیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ لیکن جن کا نام ایف آئی۔ آر میں آ رہا ہے تو ہمیں یہ چاہیئے کہ جن کا نام ایف۔ آئی۔ آر میں درج ہو تو

†[ ] Transliteration in Arabic script.

[श्री मोहम्मद सलीम]

اگر ہم وصول کرنا چاہیں اور شیگھر وصول کرنا چاہیئے تو ہمیں ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیئے کہ ان کی پراپرٹی جو ہے۔ وہ ڈائیورٹ ہو جائے۔ ہمیں جلدی سے جلدی ان کے ورودھ میں کارروائی کرنی چاہیئے ورنہ ہم جو پیسہ وشواس استھاپت کرنے جا رہے ہیں۔ بینکنگ سسٹم اور وتّے سنستھاؤں کے اوپر وہ نہیں رہے گا۔ ہمیں پچھلے دنوں کا یہ انوبھو ہے۔ منڈوڑا کیس کے بارے میں میں منتری ہونے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کتنی پراپرٹی اٹیچ کر پائے ہیں اور کتنی کر پائیں گے۔ جو ہزاروں کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے۔ اس کے اندر کتنے روپے ہم پراپرٹی کے ذریعے واپس لا پائیں گے۔ ابھی ہمارے دوسرے ورشٹھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ صرف قرقی کر دینے سے ہی وہ پیسہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کو قانونی رُخ دیکر کورٹ میں کاؤنٹر ایلیگیشن کر کے اس کو پھنسانے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے نپٹنے کے لئے آپ کیا گارڈ رکھ رہے ہیں تاکہ یہ کورٹ کے چکر میں نہ پھنس جائے۔ ساتھ ہی جو اسمال انویسٹو تھے۔ جو ڈیبازٹرس ہیں جن کو شیئر مارکیٹ کا لالچ دکھا کر جن سے

دو پیسہ کھینچ کر لایا گیا۔ ان کا پیسہ واپس کرنے کے لئے آپ کیا پربندھ کریں گے

دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اس میں ہیں ان کی کتنی پراپرٹی اٹیچ کی گئی ہے اور ان کی رقم کیا ہے۔ جو پیسہ نہیں دیا گیا ہے۔ اس کو شیگھر نپٹانے کے لئے کورٹ بننے کے بعد۔ ادھیادیش بننے کے بعد اور جب یہ ودھیک پاس کرینگے تو ہم اس کو کتنا جلدی کر پائیں گے۔ کیوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ہرشد مہتہ وغیرہ۔ میں نام نہیں لینا چاہتا۔ ان کے خلاف کچھ کارروائی کی گئی۔ کارروائی کی گئی ٹھیک ہے اور کرنی چاہیئے۔ لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو پکڑا نہیں گیا۔ ایف۔ آئی۔ آر میں نام بھی ہے پھر بھی چھوڑ دیا گیا۔ ان کے ورودھ میں کیس شروع نہیں کیا گیا یہ لوگ باہر رہ کر دستاویزوں کو اور کاغذات کو نشٹ کر رہے ہیں۔ جو پراپرٹی اسٹیٹس اور پیسہ ہے اس کو پھر سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ودیش جانے کا موقع بھی ملا ہے ایسے لوگ دیش میں رہ کر اب بھی اس پیسے کو ریچیلائز کر دیتے ہیں۔ اس کو چھپا رہے ہیں۔ دوسری جگہ ہٹا رہے ہیں۔

†[ ] Transliteration in Arabic script.

بیوروکریٹس کے نام آتے ہیں لیکن اب بھی بہت سے لوگوں کا نام آ رہا ہے اس لئے سرکار کو چاہیئے کہ وہ سلیکٹو اپروچ اختیار نہ کرے بلکہ سچائی کے ساتھ جن کا بھی نام آئے اس کو سپشٹ کیا جائے۔ جیسے وہ کہتے ہیں۔ کر کے بھی دکھائیں۔ جو بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیئے اسپیشل کورٹ کے جج نے خود کورٹ میں یہ کہا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسا کیا جا رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ سب کے ورودھ کارروائی شروع کرنے کے بجائے کچھ اسکیپ گوٹ کھوجا جا رہا ہے۔ بلی کا بکرا کھوجا جا رہا ہے۔ اس کو سامنے لایا جا رہا ہے اور باقی لوگوں کو چھوٹ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے۔ اسپیشل کورٹ کے جج کا کہنا ہے اس سے جنتا کے بیچ میں جو بھاؤنا پیدا ہوتی ہے۔ اس سے سرکار کی نیت کے بارے میں پرشن چنہہ لگ جاتا ہے۔ میں اس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ بل کے کلاز ۳ سیکشن ۲ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سیکیورٹیز ٹرانزیکشنس ہوئی ہیں۔ اسے دوران جو ایویڈنس پتہ چلے گا۔ وہ فرسٹ ڈے سے

اس کے بارے میں آپ کون سے گارڈ لینے کا پربندھ کر رہے ہیں تاکہ اس کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہاں پر سرکار کی سچائی اور ایمانداری کا بھی سوال اٹھ آتا ہے۔ ہم نے اُدیشے میں یہ کہا ہے کہ وصولی شیگھر سنشچت کریں گے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے ایف۔ ایف۔ ایس۔ ایل۔ یا پی۔ ایف۔ سی۔ کا سوال آتا ہے۔ تو جب آپ سی۔ بی۔ آئی۔ کے دوارا جانچ کروا رہے ہیں۔ کچھ نیت کا سوال اس میں آ جاتا ہے۔ سی۔ بی۔ آئی کے افسر کے اس وواد کو میں یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں۔ لیکن سرکار اس کو سپشٹ کرے کہ ایسا کوئی وواد اتپن نہ ہونے دے تو بہتر ہوگا۔ ہم نے بوفورس کے سوال پر دیکھا ہے کس طرح سے سچائی کو کورا پ کرنے کے لئے کوشش کی گئی۔ اسی طرح سے یہاں بھی ڈر اتپن ہوتا ہے حالانکہ جے۔ پی۔ سی۔ بھی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن اب تک جو کارروائی کی گئی ہے اس میں کچھ ایسے سوالات پیدا ہو گئے ہیں جس میں سرکار کی نیت کے بارے میں جنتا کے اندر کچھ پرشن چنہہ لگا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار اسے سپشٹ کرے اور واقعی اس کے پیچھے جو راج نیتک

†[ ] Transliteration in Arabic script.

آف اپریل - ۱۹۹۱ اینڈ آن آرلفور سسکھ
جون ۱۹۹۲ - یہ فرسٹ اپریل کا کیا مہتو
کیا ہے - اس سے پہلے کیوں نہیں جیسے کہ
سدن میں بھی بات چیت ہوئی اور باہر
پتر پتریکاؤں میں بھی آیا ہے کہ یہ پرتی بھوتی
گھوٹالہ تو اس سے پہلے ہی شروع ہو چکا
تھا - ریزرو بنک کے پرانے افسروں کا کہنا
ہے کہ خود ریزرو بنک کو اس بارے میں
مارچ ۱۹۹۱ میں پتہ چلا تھا تو اس سے
پہلے فرسٹ اپریل سے پہلے جو ٹرانزیکشنس
ہوا اس کے بارے میں اگر کچھ گڑبڑی ہے
تو اس کے تحت ہم کیا کاروائی کریں گے -
اسپیشل کورٹ کو آپ نے فرسٹ اپریل
کے بعد کی ذمہ داری دی ہے لیکن میں
محترمہ ہونے سے اس بارے میں سپشیفکیشن
چاہوں گا کہ اس ڈیٹ کا کیا مہتو ہے اور
اس کو پہلی اپریل ہی کیوں رکھا گیا ہے -
اتنا کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں -
"ختم شد"

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, विशेष परिस्थिति में और विशेष कार्य के लिए इस विशेष न्यायालय के गठन के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है । मैं इसका समर्थन करता हूं ।

इस विधेयक में कुछ खामियां हैं जिनके संबंध में मैं निवेदन करूंगा । लेकिन मान्यवर, इस देश में बैंक घोटाले की जो घटना हुई है यह शायद इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की अद्वितीय घटना है और इस घटना से हमारे देश का स्वाभिमान गिरा है इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है । इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जो कुछ हुआ, बैंक घोटाले में यह वित्तीय व्यवस्था में जो भी गड़बड़ की गयी इसमें इस देश के बड़े लोगों का हाथ है, बड़े अधिकारियों का हाथ है । सरकार में जो लोग शामिल हैं उन लोगों का भी इसमें हाथ है इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

मान्यवर, राष्ट्रपति जी द्वारा 6 जून को अध्यादेश जारी कर दिया गया है और 10 जून, 1992 को विशेष न्यायालय का गठन करके इसके लिए बम्बई हाई कोर्ट के जज को नियुक्ति भी कर दी गयी है । लेकिन मान्यवर, न्यायालय की तो स्थापना कर दी गयी और विधेयक पास हो जाने के बाद न्यायालय को पूरे के पूरे अधिकार हो जाएंगे इस घोटाले से संबंधित अपराधों का ट्रायल करने के लिए । अदालत तो बन गयी लेकिन मुझे संदेह है कि इस अदालत में केसेज जाएंगे कि नहीं जाएंगे क्योंकि जिस तरह का राजनैतिक हस्तक्षेप हो रहा है सी0बी0आई0 की जांच में. . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : एक मिनट आप बैठ जाइये । श्री रफीक आलम को यहां पर बैठने की सदन की अनुमति है ?

[**श्री रफीक आलम** पीठासीन हुए]

श्री ईश दत्त यादव : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि विशेष न्यायालय की स्थापना तो हो गयी और यह विधेयक पास हो जाने के बाद उस विशेष न्यायालय को सारे के सारे अधिकार भी हो जाएंगे लेकिन मुझे संदेह लगता है कि इस विशेष न्यायालय में मुकदमें जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे क्योंकि इस विशेष न्यायालय का ज्योरिसडिक्शन तभी शुरु होगा जैसा कि इस बिल के सेक्शन 6 में दिया गया है—इस विधेयक के पेज 3 की मैं दो लाइनें पढ़ रहा था :

"The Special Court shall take cognizance of or try such cases as

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

are instituted before, it or transferred to it as hereinafter provided."

इस न्यायालय में जो मुकदमें दायर किये जाएगे उन्हीं मुकदमों का यह न्यायालय निर्णय कर सकेगा । मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि इस न्यायालय में मुकदमें जाएंगे कि नहीं जाएगे इसमें मुझे संदेह लग रहा है क्योंकि बड़े राजनेताओं का हस्तक्षेप हो रहा है जांच में, माधवन का इस्तीफा प्रत्यक्ष प्रमाण है । इसलिए मैं आपके माध्यम से देश के वित्त मंत्री जी और सरकार के लोगों से कहना चाहूंगा, प्रधान मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सी0बी0आई0 की जांच या जो लोग जांच कर रहे हैं, उन लोगों की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए । अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती हैं तो न्यायालय की स्थापना करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है ।

दूसरा, मैं निवेदन कर रहा था कि प्रधान मंत्री जीने बार-बार इस सदन में और बाहर भी कहा है कि इस घोटाले से जो भी सम्बंधित होंगे चाहे वे सरकार में हों, चाहे बड़े अधिकारी हों, चाहे कोई हों उनको बख्शा नहीं जाएगा । मान्यवर, प्रधान मंत्री जी के इस कथन का मैं स्वागत करता हूं । लेकिन आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी का यह विशेष कर्तव्य है कि वह देखें कि इनवेस्टिगेशन सही-सही हो और उसमें किसी भी प्रकार का राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ।

दूसरी बात विधेयक के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा—कह दिया गया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस पर एप्लाई करेगा । परतु इस बिल के जो स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजंस हैं, इसके पैराग्राफ दो में कहा गया है—

"To deal with the situation and, in particular, to ensure the speedy recovery of the huge amounts involved."

तो धन की वसूली के लिए भी प्रोविज़न बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने पूरा विधेयक देखा है । उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अगर किसी से किसी धन की वसूली करनी होगी, तो उसके लिए इस विधेयक में क्या प्रोविज़न है—यह कहीं भी मालूम नहीं होता है । इस बात की इसमें कमी लगती है ।

इसलिए वित्त मंत्री जी को चाहिए कि वह इसके ऊपर ध्यान दें ताकि अगर यह न्यायालय में साबित हो जाए कि किसी ने धन का दुरुपयोग किया है, गबन किया है और उससे धन रिएलाइज़ करना है, तो किस विधि से और किस प्रोवीजन में यह रिएलाईज होना चाहिए ।

तीसरी चीज, मदन भाटिया जी जब बोल रहे थे, तो मैं उनकी बात का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं कि अपराध तो बहुत हुए हैं, अनेकों अपराध हुए हैं, बैंक घोटाले से संबंधित और किसी एक आदमी ने नहीं किया है और ट्रांजैक्शन अलग-अलग हुए हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि केसेज़ बहुत ज्यादा होंगे और एक ही कोर्ट रहे, एक ही जज रहे, तो इन मुकदमों के निर्णय में विलम्ब होगा ।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कई कोर्ट की स्थापना—इस तरह से कई विशेष न्यायालयों की स्थापना सरकार को करनी चाहिए ताकि इनका स्पीडी डिसपोज़ल हो जाए और जब कई विशेष न्यायालय स्थापित हो जायेंगे, तो जल्दी से निपटारा भी होगा।

चौथी चीज, जो सदन भाटिया की आशंका थी कि ट्रांसफर का प्रोवीज़न नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं इसे नल एंड वायड न डेक्लेयर कर दे, तो कई न्यायालयों की स्थापना हो जाएगी, तो सी0आर0पी0सी0 का प्रोवीज़न है ट्रांसफर आफ केसेज़ का—उनके हिसाब से अगर किसी भी व्यक्ति को जिसका ट्रायल होता होगा, उसको न्याय मिलने में संदेह होगा, तो सी0आर0सी0पी0 के अनुसार वह ट्रांसफर के लिए भी मूव कर सकेगा ।

[श्री ईश दत्त यादव]

इस संबंध में मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल के सैक्शन 9 में कहा गया है कि जो स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी, इस स्पेशल कोर्ट का अधिकार या स्पेशल कोर्ट की मान्यता सेशंस कोर्ट की तरह से होगी ।

मान्यवर, यह अच्छा प्रतीत नहीं होता और विधिसम्मत और संवैधानिक भी प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आपने विशेष न्यायालय में न्यायाधीश तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को बनाया और उनके अधिकार के बारे में कह दिया कि यह सेशंस कोर्ट का अधिकार इस्तेमाल करेंगे । इस संबंध में दूसरी बात यह होगी कि अधिकार तो उनके सेशंस कोर्ट के होंगे, लेकिन उनके फैसले के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। बीच में हाई कोर्ट को इग्नोर किया जा रहा है ।

इसलिए मेरा निवेदन है कि ट्रायल का तो जो प्रोविजन है, या ट्रायल की सी०आर०पी०सी० में जो विधि है--(समय की घंटी)--उसके अनुसार करें, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस विशेष न्यायालय की स्थापना आपने की है, उस विशेष न्यायालय का अधिकार आपको हाई कोर्ट का अधिकार देना चाहिए । जो सैक्शन 9 में कहा गया है कि वह सैशंस कोर्ट का अधिकार होगा, वह सेशंस जज का अधिकार न होकर के हाई कोर्ट का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यदि आप सेशंस कोर्ट का अधिकार उन्हें देते हैं, तो बीच में मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर पहली अपील, फर्स्ट अपील इस निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में करनी पड़ेगी और फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

इसलिए मेरी आपके माध्यम से दर्खास्त है कि इस पर सरकार को गौर करना चाहिए और इस पर विचार करके यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए

अंतिम चीज मैं कहना चाहता हूं, मान्यवर, कि इस पूरे विधेयक में कहीं समय की बाध्यता नहीं रखी गई है । कि विशेष न्यायालय में जब मुकदमा दायर हो जाएगा चार्जशीट सबमिट हो जाएगी, तो कितने समय में वह न्यायालय इसका निर्णय करेगा क्योंकि अन्य जो कानून हैं, मान्यवर, उसमें इस तरह का विधान है, इस तरह के प्रोविज़न हैं कि इतने समय के अन्दर इस बात का या इस मुकदमें का निर्णय हो जाना चाहिए । लेकिन यह जो विधेयक लाया गया है इस विधेयक में उस न्यायालय को कुछ नहीं कहा गया है कि कितनी अवधि के भीतर इन बातों का वह निस्तारण कर देंगे और समय की बाध्यता नहीं है तो संभव है कि ज्यादा समय लगे और चूंकि इस तरह का यह सनसनीखेज विषय है....

उपसभाध्यक्ष (श्री रफीक आलम) : अब आपका समय समाप्त है ।

श्री ईश दत्त यादव : मैं आपकी आज्ञा मान रहा हूं । केवल एक मिनट समय और लेना चाहता हूं । क्योंकि अगर समय का निर्धारण नहीं किया जाएगा, कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा कि कोर्ट इतने समय के अंदर अपना निर्णय दे दे, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, यह असाधारण है, इसीलिए स्पेशल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता पड़ी । यह केवल इस देश का विषय नहीं है यह दुनियां की चर्चा का विषय है और अगर लंबी अवधि तक केसेज़ पैंडिंग रह जायेंगे तो इसका महत्व ही समाप्त हो जाएगा और जो दोषी लोग हैं ये दोषी लोग किसी न किसी तरह से सजा से बच जायेंगे गवाहों को तोड़ करके, टेंपरिंग विटनैसेज़ का करके और किसी न किसी तरह से बचने का ये प्रयास करेंगे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रफीक आलम) : अब आप तारीफ रखिए । चतुरानन मिश्र जी, 3 मिनट समय है ।

श्री ईश दत्त यादव : मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रफीक आलम) : जरा जल्दी कीजिए, क्योंकि टाईम बहुत कम है ।

श्री ईश दत्त यादव : ठीक है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इस संबंध में सरकार की तरफ से अभी कोई नियमावली नहीं बनाई गई है। मैं चाहता हूं, मेरा अनुरोध है कि सरकार की तरफ से जब अध्यादेश जारी कराया गया सरकार की तरफ से जब इस विधेयक को लाने के लिए तैयार किया गया तो चाहिए था कि इस संबंध में जो रूल्ज हैं, नियमावली है, उसको भी तैयार कर लेना चाहिए। अब आपकी आज्ञा का मुझे पालन ही करना है आपके माध्यम से केवल एक बात का मैं अनुरोध करना चाहता था और हमारे वित्त मंत्री जी बैठे थे, चले गए, मैं उन्हीं से कहना चाहता था कि इस देश के वित्त मंत्री के माथे के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है और इनको चाहिए था कि जब इस तरह का घोटाला प्रकाश में आए और इस देश में नहीं, दुनिया में चर्चा का विषय बने तो इनको आदर्श उपस्थित करना चाहिए था। मैं वित्त मंत्री जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो नैतिकता का तकाजा था, जो ईमानदारी का तकाजा था, उनको वित्त मंत्री के पद से त्याग-पत्र जरूर देना चाहिए था। उन्होंने वित्त मंत्री के पद से त्याग-पत्र न दे करके दोषी व्यक्तियों को बचाने की कोशिश की है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि अब भी बहुत समय है, भारत सरकार के वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को, इस इतनी बड़ी घटना पर जो दुनिया में चर्चा का विषय हो, अपने पद से त्याग-पत्र दे करके एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री रफीक आलम) : श्री चतुरानन मिश्र जी। तीन मिनट।

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभाध्यक्ष महोदय, जब हम लोगों ने इस विधेयक को नामंजूर करने का प्रस्ताव दिया था तो इसलिए नहीं कि आर्डिनेंस नामंजूर हो जाए बल्कि पार्लियामेंटरी मैथड वह ही एक तरीका है बहस में लाने का इसीलिए हमने दिया था। मैं उन माननीय सदस्यों के साथ नहीं हूं जो समझते हैं कि इस सवाल पर आर्डिनेंस नहीं जारी होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ऐसी पूर्ण यह परिस्थिति थी जिसमें इस तरह का आर्डिनेंस जारी होना चाहिए था नहीं तो आखिर इन लोगों को पकड़ा कैसे जाएगा? साधारण कानून से पकड़ना और रुपया वसूल करना संभव नहीं था। मुझे तो शक है कि अभी भी संभव नहीं है। जहां तक इस बिल पर आने के पहले माननीय सदस्य जो हमारे अधिवक्ता भी हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं भाटिया जी ने जो एक-दो प्रश्न उठाए हैं, मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि इसको अगर आपको जल्दबाजी है इसे आज ही पास करा लेने के लिए और फिर आने के लिए, जब सब रिहा हो जाएं, तब तो दूसरी बात है, नहीं तो आप लीगल ओपीनियन ले लीजिए। क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, तो मैं भी सोच रहा हूं। फिर से मान लीजिए कि यह लिखा हुआ है कि इसमें फर्स्ट अप्रैल से ले करके ही, तो मैं बराबर सोच रहा था कि यह फर्स्ट अप्रैल क्यों रखा है इन्होंने, तो मुझे इसको छोड़ करके और कोई अर्थ नहीं लगा कि यह अप्रैल फूल्ज डे है जो सभी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है इसीलिए सरकार ने शायद यह डेट दे दिया है। कि सब तो छूट ही जाएगा। फिर बाद में होगा कि यह हो गया, वह हो गया। . . . **(व्यवधान)** . . .

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दलबीर सिंह : ऐसा नहीं है।

श्री चतुरानन मिश्र : ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं है तो आप बता दीजिएगा कि यही डेट आपको कहां से मिली? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमको नहीं मालूम है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं।

मान्यवर, फिर कुछ बातें हैं, जिसकी तरफ हम सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे इस कानून की तरफ और दूसरे बिन्दुओं की तरफ भी और वह यह है कि दो तरह के काम बकायदा हुए। एक तो हुआ है स्टॉक मार्केट में, शेयर स्टॉक में और दूसरा हुआ मनी मार्केट में, जहां बैंक हैं वहां। अपराधी दोनों जगह हैं।

[श्री चतुरानन मिश्र]

अब हम देख रहे हैं कि आप जो यह कानून बना रहे हैं उससे क्या उनको पकड़ा जा सकता है ? आपने जो रास्ता तय किया है, उसमें क्या उनका कसूर है ? अगर किसी ने यह शेयर का पैसा बढ़ाया शेयर खरीदा तो कहां जुल्म कर दिया है ? जो बैंक रिसीप्ट वाली पद्धति है, सो तो है पद्धति, कहां से यह इल्लीगल हो जाती है ? किस स्टेज पर हो जाती है ? लॉ में कहीं डिफाइन नहीं है । जो डिफाइन है उसका आप जिक्र नहीं करना चाहते या उस पर एक्शन नहीं लेना चाहते । जैसे, मान लीजिए, अखबारों में यह बात आई है कि फोर्जड रिसीप्ट के आधार पर काम किया गया । इसके लिए स्पेशल कोर्ट की जरूरत नहीं थी । यह तो डिपार्टमेंटल एक्शन लेकर के भी उस आदमी को नौकरी से हटा देते या जो अरेस्टेड लोग हैं, जेल में 48 घंटे से ज्यादा हैं, उनको नौकरी से सस्पेण्ड कर सकते थे या दूसरी प्रोसीडिंग कर सकते थे । इसलिए आपकी ईमानदारी पर लोगों को शक हो रहा है । इसलिए हमने अप्रेल फूल की बात कही क्योंकि हमको लग रहा है कि इनको कैसे पकड़ा जाएगा ।

दूसरा, कुछ विदेशी बैंक और कुछ विदेशियों ने इस काम को किया । हमारा लॉ उन पर गवर्न होगा या नहीं होगा ? यह बात भी हमको स्पष्ट नहीं लगती है कि इस तरह का होगा । हमारे लॉ मंत्री जी हैं, यह बताएंगे कि ऐसा प्रोवीजन है या नहीं है ? या फिर, आप उनको छूना नहीं चाहते क्योंकि और विदेशी पूंजी लाने के लिए आप फेर में हैं और इसलिए सोचते हैं कि छोड़ो इन लोगों को, इधर-उधर करके ऐसे सफेद किया जाए । इस तरह से यह जो शेयर मार्केट का धंधा है, उसमें तो आर्टिफिशल शेयर का भाव बढ़ाया ही जाता है । इसमें अपराध क्या है ? यह तो आप एलाऊ किए हुए हैं, सारी दुनियां में एलाऊ है, जहां-जहां पूंजीवादी व्यवस्था है, हर जगह एलाऊ है । बाद में आप एक स्टेज पर जाकर कहेंगे कि यह इल्लीगल होता है । यह तो लॉ में हमारे डिफाइन नहीं है तो हम उनको कैसे पकड़ेंगे ? यह तो आप हमको बता दीजिए ।

दूसरी बात, जिस पर सरकार पर शक हो रहा है, वह यह कि एफ. आई. आर. में जिनका नाम आया है उन पर कार्यवाही नहीं की गई है । क्योंकि सुना है, वह ए. आई. सी. सी. के मैम्बर हैं या क्या हैं, अखबारों में यह बात आई है, मेरे पास कुछ तथ्य नहीं हैं । त्रिवेदी जी बोल रहे थे चतुर्वेदी जी के बारे में, तो त्रिवेदी से चतुर्वेदी की बात आ गई तो और भी गंभीर बात हो जाती है, अगर मिश्र जी गवाह हों तो फर्दर जोर देने की बात हो जाती है । तो आप इसको कहिए कि क्यों नहीं पकड़े गए ? फिर, एक ओकर थे भूपेन्द्र, सुना है, वह तो नाम ही रखे हुए हैं दलाल, अब आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं । कहां चला गया, देश गया या विदेश गया ? यह सब जानकर आप पर शक होता है ।

फिर, इसके लिए आपको क्या दिक्कत है कि बिना सिक्योरिटि के कैसे बैंक रिसीप्ट ज्यादा दे दिया, यह तो नॉलिज में आ गया । आपको डिपार्टमेंटल एक्शन लेने में क्या दिक्कत है ? तो यह मिल-मिलाकर हमको ऐसा लगता है कि एकाउण्ट का रिकन्साइल करना बैंक में अत्यधिक असंभव सा काम है, जब आप कम्प्यूटर में लाइएगा तब देखा जाएगा, वह रिकन्सायल होता नहीं है । आप किसी पर मुकदमा चला नहीं पाएंगे । पहले भी इनका रिकन्सायल नहीं था, 80,000 करोड़ का, 85,000 करोड़ का, कुछ-कुछ हम जानते हैं इसलिए आपको कह रहे हैं । तो कहें कि हमारा क्या कसूर था, इनके पास साधन नहीं था । यह कितने लूप-होल हैं । इनको भागने के बहुत ज्यादा मौके हैं ।

हमारे यहां से हमारा कानून इस ढंग से है कि ईमानदार कम काम कर सकता है और बेईमान बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है । यही हमारी

लीगल व्यवस्था भी है और कुछ इस तरह की पद्धति भी है। अब आपने कहा कि स्पीडी ट्रायल...(**समय की घंटी**)...सर, दो-तीन मिनट और दीजिएगा। स्पीडी ट्रायल का आपने देखा कि स्वागत होगा कि स्पीडी ट्रायल हुआ, लेकिन होगा कैसे स्पीडी ट्रायल? जितना कानून है, संविधान है, उसको छोड़कर के तो यह अलग से नहीं जाएगा। क्या आपको यह अधिकार था या आप कर सकते हैं कि ट्रायल की अवधि निश्चित कर दें कि इतने दिनों के अंदर इस केस का डिस्पोजल कर दीजिए। और क्या सरकार के पास यह तथ्य जमा है, हम नहीं जानते? क्या सी. बी. आई. अभी तक पहुंच गई है, इतना रिकार्ड आ गया है कि उनका कन्विक्शन श्योर हो जाएगा, अन्यथा ट्रायल ही होकर क्या होगा? जब सब छूट ही जाएंगे तो उसमें ट्रायल क्या करेंगे? तो इसी लिए मालूम नहीं पड़ रहा है। इसी तरह से अपील केसिस का जो डिस्पोजल होगा, उसमें लोगों को मालूम है कि एक-एक केस को 20, 25, 30 बरस लग जाते हैं, वह आदमी मर जाता है, केस चलता रहता है। तो इसको देखते हुए उसका भी आपने टाइम लिमिट नहीं किया है। फिर आप कह रहे हैं कि स्पीडी डिस्पोजल होगा, इसका तो कोई लक्षण लग नहीं रहा कि इसका यह हो सके। दूसरी बात, कोर्ट अगर जस्टिस करना चाहे और चाहता ही है तो उसके लिए उसको मदद देने की बात है। तो आपने कहीं प्रोविजन तो नहीं रखा है कि इस तरह के केसिज में जो टैक्निकल मेनूवरिंग्स होती हैं, उसके लिए एक्सपरटाइस कोर्ट को भी उपलब्ध कराया जाए इंडिपेंडेंट ताकि कोर्ट जल्द से जल्द बातों को समझ सके, नहीं तो वही पेशकार और वही मंशी लेकर करेगा तो उसको तो समय लगेगा। और हमने कहा कि आप जो व्यवस्था ला रहे हैं उसमें हमको देखने से पता चला, सरकार अपना कुछ पैसा बचा ले, बचा नहीं सकती है, वापिस करा नहीं सकती है, कुछ टैक्स भी रिकवर हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं आर्टिफिश्यली बहुत हाई दाम पर, उनको सरकार वापिस करेगी यह असंभव बात है। क्योंकि सरकार ने तो आज तक हिसाब भी नहीं दिया है कि वह रुपया कितना है। यह जो आप तीन या चार हजार करोड़ रुपया दे रहे हैं, यह तो दे रहे हैं, जो आपके रुपए का घोटाला हुआ है—बैंक का, इसका, उसका, यह हिसाब दे रहे हैं लेकिन वह कितनी रकम है यह तो कोई जानता नहीं। इसलिए उसके लिए काहे को उनको दिलासा दे रहे हैं कि उनका आप वापिस कर सकेंगे। यह तो होता नहीं है। यह एक तरह का जुआ है, जो लीगल जुआ है—शेयर मार्किट—हम लोग अलाउ किए हुए हैं। इसलिए उनको तो संतोष करके बैठ जाना होगा, वह इसका प्रावधान नहीं कर सकते। दूसरे आपने इजाजत दी है हमारे देश में कि रुपए को तुरंत विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले हवाला मार्किट में होता था, यह होता था, अभी भी होता है, वह कर लिया होगा अगर वह निश्चित रूप से चोर था तो, वह इसलिए तो नहीं बैठा था कि वित्त मंत्री जी बिल लाएंगे और आप सभापति रहेंगे और चतुरानन मिश्र भाषण करेंगे, उसके बाद कानून पास होगा, तब हम चोर आकर इसको करेंगे। ऐसा कोई बेवकूफ चोर नहीं होगा और अगर होगा तो सब कुछ हटा लिया होगा इधर-उधर, थोड़ा-सा बचा गया होगा। इसलिए एन्टायर लीगल सिस्टम जो है जिस ढंग का, उसमें हम लोग कैसे कर सकते थे। हम चाहते थे कि थोड़ा-बहुत इस लॉ के अंदर प्रोविजन कर दें नहीं तो स्पेशल कोर्ट का कोई महत्व नहीं रह जाता।

अंत में, उपसभाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि यह तो ठीक है कि हम लोग विरोधी पक्ष में हैं इसलिए आपको कहते हैं कि आप गड़बड़ी कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, यह सब जायज है, लेकिन समस्या यह है कि बाहर जाकर लोग कहते हैं कि आखिर पार्लियामेंट क्या

[श्री चतुरानन मिश्र]

बिगाड़ लेगी ? बोफोर्स में क्या किया जे०पी०सी० ने ? इसमें जे०पी०सी० क्या करेगी ? हम उनकी मंशा में, ईमानदारी पर कोई डाउट नहीं करते, हम जानते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, सभी माननीय सदस्य हैं। लेकिन अच्छे लोग बुरे लोगों को पकड़ नहीं सकते हैं यह भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि जो बहुत बुरे लोग होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। तो हम लोगों पर भी यह आ रहा है कि आप लोग पार्लियामेंट में बैठकर करते क्या हैं? इसलिए जो अट-स्टेक है, वह सिर्फ मनमोहन सिंह जी का अट-स्टेक है, कांग्रेस गवर्नमेंट का अट-स्टेक है, ऐसी बात नहीं है, पार्लियामेंट की पद्धति का अट-स्टेक है कि इतने-इतने हजार करोड़ रुपए खाकर भी कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति आज हमारी हो गई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह कानून जो आप बना रहे हैं तो कम से कम ऐसा बनाए कि तुरंत अल्ट्रावायरस नहीं डिक्लेअर हो जाए, नहीं तो हम लोग सब भ्रष्ट के साथ समझे जाएंगे, इस कानून के जरिए से। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि सरटेन प्रोविजंस के बारे में कुछ उन्होंने सवाल उठाया है और कुछ लगती भी है उस तरह की बातें, तो इसलिए आप उनके भी नेच्यूरल अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका उल्लंघन तो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको देखते हुए इस कानून को बनाएं और कुछ जो हमने आपसे कहा है, जो आप डिपार्टमेंटल एक्शन खुद ले सकते हैं—चाहे फोर्जड बी०आर० हो, चाहे बिना इसके हो—मौर ए-इवांस के लिए रुपया दे दिया, सिक्यूरिटी का रुपया दे दिया, बिना सिक्यूरिटी के कर दिया, ये सब चीजें जो हैं या 48 ऑवरस तक जेल में रहने के बाद भी आपने सस्पेंड नहीं किया है तो इन सबका जवाब तो दीजिए ताकि हम लोग यह पूछ सकें कि सरकार सीरियस है ? क्योंकि भाषण में आप जितने सीरियस हैं, एक्शन में नहीं हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको कीजिए क्योंकि हम सब की प्रतिष्ठा—आपकी, पूरे सदन की, पूरे पार्लियामेंट की, अट-स्टेक है। इसलिए इसको बचाइए, यही मुझे कहना है।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान : (आन्ध्र प्रदेश) : वाईस चेयरमेन सर, अभी हाल में हजारों-करोड़ रुपयों का जो बैंक का घोटाला हुआ है, उस बैंक के घोटाले के जो मुलजमीन हैं, उनको सजा देने के लिए एक फौरी तौर पर 6 जून को एक आर्डिनेंस निकाला गया था और उस आर्डिनेंस को एक एक्ट की शकल देने के लिए यह बिल लाया गया है। इसका मैं खैर मकदम जरूर करता हूं। मगर साथ ही साथ इत्तफाक से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी यहां मौजूद है और हमारे मिनिस्टर आफ स्टेट फार लॉ भी यहां पर मौजूद हैं। मैं आपके जवाब में यह जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो स्पेशल कोर्ट के जरिए आप इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुलजमीन हैं उनको सजा दे दी जाए और फिर साथ ही साथ अभी हाल में एक जोइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी है और वहां भी इसकी पूरी तहकीकात चल रही है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वक्त वाहिद में या सिमलटेनिसली स्पेशल कोर्ट भी जांच करेगी और जोइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी तहकीकात करेगी। तो क्या यह नेच्युरल जस्टिस के एन जो हैं

मुताबिक है? इस वजह से जो मुलज़मीन, जो एक्यूज्ड हैं, वह बराबर इस बात का एतराज़ कर सकते हैं कि जो कुछ भी हमको प्ली लेना है और जो कुछ भी हम फेस कर रहे हैं वह स्पेशल कोर्ट में भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जोइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़रिए भी तहकीकात हो रही है। इस ताल्लुक से मैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल को पास करने से पहले आप अच्छी तरह कानूनी राय ले लीजिए कि क्या यह पौसिबिल है? इसके पास करने में यदि एक दिन या दो दिन की देरी हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। मगर एक दफे आप पास करेंगे, फिर यह बिल किसी न किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में अगर चेलेंज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस बिल को नल एंड वोइड करार दे दे तो फिर खामोखां की जो इतनी मेहनत होगी, वह मेहनत बिल्कुल रायगां चली जाएगी और जाया होगी। लिहाजा मैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल को आज ही पास करने से बेहतर बात यह है कि इसके ताल्लुक से अटार्नी जनरल की कानूनी राय ले ली जाए, इस वजह से कि उससे पहले यह बिल इंटरोड्यूज हुआ था और फिर उसके बाद लोक सभा में पास हुआ और फिर साथ ही जोइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। तो जाहिर है कि जोइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की वह अपने बराबर सजेशंस जारी रहेंगे और फिर इसमें जो एक्यूज्ड है वह बराबर स्पेशल कोर्ट में जाएंगे और इसको फेस करेंगे। यह एक ही बात मेरे जहन में आ रही थी, मैं इसकी वज़ाहत चाहूंगा और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इसको आप जरूर अपने जवाब में पूरा हमको मुतमईन करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।

श्री محمد خلیل الرحمٰن: آنریبل وائس چیئرمین سر۔ ابھی حال میں ہزاروں کروڑ روپیوں کا جو بینک کا گھوٹالہ ہوا ہے اس بینک کے گھوٹالے کے جو ملزم ہیں ان کو سزا دینے کے لئے ایک فوری طور پر ۶ ججوں کو ایک آرڈیننس نکالا گیا تھا اور اس آرڈیننس کو ایک ایکٹ کی شکل دینے کے لئے یہ بل لایا گیا ہے اس کی میں خیر مقدم ضرور کرتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ ہی اتفاق سے ہمارے فائنینس منسٹر صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ فار لا بھی یہاں موجود ہیں۔ میں آپ کے جواب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف تو اسپیشل کورٹ کے ذریعے آپ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ملزم ہیں ان کو سزا دے دی جائے اور پھر ساتھ ہی ساتھ ابھی حال میں ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھی ہے اور وہاں بھی اس کی پوری تحقیقات چل رہی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وقت واحد میں یا سائمل ٹینیسلی اسپیشل کورٹ بھی جانچ کرے گی اور جوائنٹ کمیٹی بھی تحقیقات کرے گی۔ تو کیا یہ نیچرل جسٹس کے اصول کے مطابق ہے۔ اس وجہ سے جو ملزمین ہیں جو ایکیوزڈ ہیں وہ برابر اس بات کا اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کو ملی لیسی ہے اور جو کچھ بھی ہم فیس

†[ ] Transliteration in Arabic script.

کر رہے ہیں۔ وہ اسپیشل کورٹ میں
بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جوائنٹ
پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعہ بھی تحقیقات
ہو رہی ہے۔ اس تعلق سے میں ہمارے
فائنینس منسٹر صاحب سے یہ درخواست
کروں گا کہ اس بل کو پاس کرنے سے
پہلے آپ اچھی طرح قانونی رائے لے لیجئے
کہ کیا یہ پاسیبل ہے۔ اس کے پاس کرنے
میں اگر ایک دن یا دو دن کی دیری ہو
جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مگر ایک
دفع آپ پاس کریں گے پھر یہ بل کسی نہ
کسی وجہ سے سپریم کورٹ میں اگر چیلنج
کیا جائے اور سپریم کورٹ اس بل کو
نل اینڈ وائڈ قرار دے دے تو پھر جو انویسٹی
گیشن جاری رہیں گے اور پھر اس میں
جو اکیوزڈ ہیں وہ برابر اسپیشل کورٹ
میں جائیں گے اور اس کو فیس کریں گے
یہ ایک ہی بات میرے ذہن میں آ رہی
تھی میں اس کی وضاحت چاہوں گا اور
فائنینس منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا
کہ اس کو آپ ضرور اپنے جواب میں پورا
[illegible]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAFIQUE ALAM): I seek the permission of the House for Mr. Sukomal Sen to occupy the Chair.

[SHRI SUKOMAL in the Chair]

SHRI TAA CHARAN MAJUMDAR (Assam): While agreeing with the general purposes of the Bill, I will try to draw out some vagueness and defects in the Bill.

The purpose of the Bill is to see that the cases before the special courts are disposed of expeditiously. In this Bill a provision has been made that the presiding officer of the special court will be a judge of a High Court. The High Courts are already over-burdened with work. There are rising arrears. If a High Court Judge is to sit only for trying these special court cases, arrears is the High Courts will further increase. I would like to know whether the purpose of the Government is to provide for a sitting judge continuously for a special court, or it wants that the High Court Judge presiding as a judge of the special court will have his attention divided between the Bench and he special courts. That is the point to be taken into consideration. If the High Court judge is to look after his work in the High Court Bench and also has to sit as a judge in the special court, the purpose of

† [] Transliteration in Arabic Script.

speedy disposal of cases before the special Courts will not be achieved. Moreover, the High Court Judges will be overburdened. So, my humble suggestion is that the Government should make provisions for appointing some retired judges of proven efficiency and integrity to sit as whole-time judges in the special courts. That will help in the speedy disposal of cases.

The offences to be tried by the special courts will be offences covered by the Indian Penal Code. This Bill does not make clear why ordinary courts are not adequate in the disposal of those cases. This thing should be made clear in the Bill.

I would draw the attention of the Government to another apparent contradiction in Section (9), wherein it has been provided:

> 9(2): "Save as expressly provided in this Act, the provisions of the Code shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, apply to the proceedings before the Special Court and for the purposes of the said provisions of the Code, the Special Court shall be deemed to be a Court of Session, and shall have all the powers of a Court of Session, and the person conducting a prosecution before the Special Court shall be deemed to be a Public Prosecutor."

My submission is that a Public Prosecutor is to be appointed under Section 24 of the Criminal Procedure Code. Simply making a provision that a person conducting prosecution before Special Courts would be deemed to be a Public Prosecutor, will, according to my humble submission, lead to legal complications. In order to authorise a man to conduct the prosecution before a Special Court, he must be a person authorised under Section 24 of the Criminal Procedure Code. It appears as if the intention of the Bill is to allow some other persons, who are not appointed under the provisions of Section 24 of the Criminal Procedure Code to be Public Prosecutors. If that is the intention of the provision, I think some legal complications will arise. The law requires that a Public Prosecutor must be one who is appointed under Section 24 of the Criminal Procedure Code.

Another submission is consideration of the fact that the persons to be tried before the Special Courts are very influencial persons. They have got heavy funds at their disposal and they will hire the topmost lawyers of the land. In order to meet the challenge, my submission would be that there should be a panel of competent lawyers and lawyers of integrity to act as Special Public Prosecutors appointed under Section 24 of the Criminal Procedure Code. That should be done for the successful conduct of the cases before the special courts.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKOMAL SEN): Since it is your maiden speech, I have allowed you more time. Now please conclude within two or three minutes.

SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Some points were raised by some hon. Members regarding the transfer of cases before the Special Court. I think the purpose of the Bill is to have so many Special Courts in different parts of the country. When the Bill has made provisions for application of Criminal Procedure Code, there will not be any difficulty in seeking transfer of cases from one special court to another. It is so because the Criminal Procedure Code provides that the Supreme Court has wide powers to transfer one case from one criminal court to another criminal court. When the Special Courts are also Criminal Courts, there will be no bar in seeking transfer of cases from one Special Court to another, if the accused in any way think that they will not get justice from a particular criminal court.

[Shri Tarachand Majumdar]

Some hon. Members were commenting that the Special Courts will be regarded as Sessions Courts and when a high Court Judge is presiding over a special Court and will be dealing with such cases, he will be lowered in his status. I think that is not the purpose of the Bill. It is to provide that the procedure followed in the Session Court will also be the procedure followed in the Special Court.

The Bill has made provision for one appeal *i.e.* appeal before the Supreme Court. In that way it has curtailed the right of the accused person for the benefit of one appeal.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (Nominate): Options are allowed in that.

SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: In ordinary cases the accused person generally gets two appeals. Over and above that he has a right to seek revision. From the Bill it appears that the procedure followed in the trial of general cases has been kept in tact.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKOMAL SEN): You have taken more than double your time. You have already taken twelve minutes. Please conclude within one minute.

SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: O.K. I conclude. I don't want just to over-step my right.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKOMAL SEN): Anyway, you can conclude your sentence.

SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: If the purpose of the Bill is to see that the cases are disposed of expeditiously, I think nothing much will be achieved because the speedy disposal of cases depends on the investigating agency, the prosecuting agency, the Court and the defence lawyers. Unless all these persons cooperate, there cannot be any speedy disposal. An hon. Member referred to a very important point that the Bill should have provided for a time-limit for disposal of cases. I think that could have been done. The Bill could have also provided that the hearings before the Special Court will continue from day to day. Some such provision should have been made in the Bill if the purpose of the Bill is to see that the cases before the Special Court are to be expeditiously disposed of. So, my suggestion is that if the intention of the Government is to see that cases are speedily disposed of, this provision may be incorporated in the Bill. Thank you.

SHRI MADAN BHATIA: Sir, with your permission, may I take just one minute? I would like to have your permission to mention one point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKOMAL SEN): You have already spoken. One more speaker is there. Let him finish first. Mr. Ambedkar. You have six minutes.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): You can take one minute more.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR): Mr. Narayanasamy is generous with me.

Mr. Vice-Chairman, Sir, there are now six agencies investigating into the scam. They are the CBI, the Revenue Intelligence, the local police, the Income-tax Department, the JPC and now the Special Court. I do not know where all these agencies are going to land us, or what is going to happen if these investigating agencies come to different conclusions. Are you again going to have another Committee to check up the recommendations of these agencies and to come to a decision as to which agency is right? I do not know what the Finance Ministry is up to.

There is one more disturbing factor which has come out. There have been reports in the press that there was some delay in arresting some of the persons or information being passed on by one agency to another and that delay has been used either to destroy some of the papers that were available or for the

flight of money from this country to other countries. And, they say that the media that were used were the foreign banks. May I know from the hon. Minister whether they are looking into this aspect?

I will again come to another issue on which I would like the Finance Minister to be very precise. A piece of information, a story, has been circulated in Bombay that there was one Revenue Intelligence Officer, by name Mr. Rai. When Harshad Mehta gave an interview to the Eyewitness cassette, it was 15 days after he started investigating the whole case. He said that he had investigated into the whole matter somewhere in the end of April or the beginning of May and his report was complete and that the report was submitted to the Finance Department. The Finance Department had showed that report to the Prime Minister and all of a sudden we found that in the month of June or at the end of May, the Revenue Intelligence Officer, Mr. Rai, who was investigating into the case, was transferred from Bombay to Calcutta. I would like to know from the Finance Minister whether this information or the story that is being told in Bombay is true or not. (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): This is all gossip which has no substance.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: I know this is all gossip. But I would like to know whether Mr. Rai, an intelligence officer, who was working in Bombay, has been transferred to Calcutta. As per my information, till April, he was posted at Bombay. In June, he has been transferred to Calcutta. Has transfer taken place? If so, why are the transfers taking place so fast? The hon. Finance Minister denied this report. Some of the hon. Members have got a copy of the circular. Some of the Members who have been making allegations both inside the House and outside, are waiting for the Finance Minister to make a categorical statement. They are waiting to see how far these agencies are being manipulated. Already, in one of the judgements, a judge has commented about the functioning of some of the governmental agencies. I would not like to go into that. I think those Members who are having a copy of this circular, are holding it to see as to how far the Government is true on it.

Lastly, whatever scam has taken place, those who are found guilty, will be dealt with according to the law of the land. The law will take its own course and they will be punished accordingly.

Coming to shares, what is the Government going to do about shares? You have asked the RBI to hold up some of the dealings which have taken place. Basically, forward dealing was one of the reasons for this. I don't think it is time for us to withdraw those steps which we have already taken. We are disrupting the market economy which was established. I know there are scams which have taken place in the world. But they have taken remedial measures. I would like to know whether the Finance Minister is going to address himself to the problems of those share brokers who have been blacklisted or those shares which have been blocked or some of the banking processes which have been stopped. Will he take a decision regarding these? There is a total blockade of the money; there is a total blockade of the capital market and some of them are now selling them at a distress price. I would like to know when the Finance Minister is going to decide the whole matter. If he is going to decide the whole matter. If he is going to ask the JPC to look into this, then we will have to have another scam because this is what is known as short selling and then we will have another JPC to find out how the short selling has taken place and this will be an unending process. The Finance Minister should address himself to this and take a quick decision. Thank you.

SHRI MADAN BHATIA: I am grateful to you for giving me just one or two minutes. There was one point which

(Shri Madan Bhatia)

escaped my mind when I was speaking on this Bill. Clause 4 of this Bill says: "If the Custodian is satisfied that any contract or agreement entered into at any time after the 1st day of April, 1991 and on or before the 6th June, 1992 in relation to any property of the person notified under section 8, has been entered into fraudulently or to defeat the provisions of the Act, he may cancel such contract or agreement." Now supposing, the person who is contemplated by clause 4 has gifted away his property during this period to his children or to his wife or to his relations or to his friends, that gift is not covered by clause 4 because gift is neither a contract nor an agreement. That will mean the property which he has gifted away, will completely escape the jurisdiction of the custodian. It will go out of the hands of the authority which is being constituted under this Bill. In order to seize and attach that property 5.00 P.M. and keep it under safeguard for the purpose of meeting various liabilities after that person is convicted because it is neither a contract nor an agreement and the properties gifted away to the sons and the relation completely escape. That's all.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKOMAL SEN) Now, according to the List of Business we have to take up two statements by Ministers, one by Shri Ajit Kumar Panja and another by Shri M. M. Jacob. It is 5 o'clock. If the House agrees, then the Ministers can make the statements and the clarifications can be taken up later on. After that, we can resume the discussion on the Bill because we will have to get the Bill passed today itself. Clarifications can be taken up tomorrow and we can complete the Bill today.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL (Gujarat): That will do... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKOMAL SEN): It is all right. ... (*Interruptions*)...

AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): The Minister can reply now in four or five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKOMAL SEN): All right. If you agree, the Minister can reply now. We can complete the Bill then. Mr. Mathur, mover of the Resolution, absent. Mr. Minister.

श्री दलबीर सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, स्पेशल कोर्ट बिल में माननीय सदस्यों की ओर से बहुत से सुझाव आए हैं और बहुत सी चीज़ों की जानकारी भी हमें मिली है । खास कर के एक मुद्दे को ले कर जो भाटिया जी ने भी उठाया तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा कि 1-4-1991 की बात क्यों कही गई है । कोई भी स्पेशल लेजिस्लेशन हो उसकी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिये और जहां तक 1-4-1991 का सवाल है जानकीरमन कमेटी ने 1-4-1991 के पश्चात ही जांच की है, इसलिए 1-4-1991 रखी है । इन केसेज़ को निपटाने के लिए स्पेशल लेजिस्लेशन जो लाया गया है इसलिए टाइम-फ्रेम इसमें 1-4-1991 का इसमें रखा गया है और इसके साथ साथ 6 जून को आर्डिनेंस जारी किया गया । मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि इस बिल को लाने के पहले इस को बहुत गहराई से देखा गया । एटोर्नी जनरल से राय भी ली गई और हमारे जो कानून के ज्ञाता हैं उनसे भी बात की गई । इतना ही नहीं हमारे जो अपोज़ीशन पार्टीज के लीडर्ज हैं उनसे अभी सात अगस्त को इस बिल के ऊपर विचार-विमर्श भी हुआ । स्वयं सरकार यह चाहती है कि कोई भी क्लाज़ ऐसी न हो जिसका लाभ उठा कर कलप्रिट छूट जाए । जहां तक स्पेशल कोर्ट का सवाल है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में क्यों नहीं ले जाना चाहिये, इस सवाल पर भी बड़ी गहराई से विचार किया गया । इस लिए इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें हैं वह लाई गई हैं ताकि केसों का स्पीडी डिस्पोज़ल हो, जैसे कि आपने भी कहा

है कि वर्क को जल्दी निपटाया जाए । इसलिए मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि जो मुद्दे उन्होंने यहां पर उठाए हैं, मेरे विचार से सभी सदस्यों की इस बात के प्रति सहमति है और इसको मैं मानता हूं कि इस देश में यह विशाल धोखाधड़ी हुई है । इस धोखाधड़ी के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी । जैसे ही यह प्रकरण सामने आया, जानकीरमन कमेटी की रिपोर्ट आई, आर्डिनेंस यहां पर लाया गया । इतना ही नहीं कस्टोडियन भी बैठाया गया । इसके साथ साथ जैसे कि श्री ईश दत्त यादव ने कहा है कि इसके रूल्ज बनने चाहियें, नियमावली भी बननी चाहिये। नियमावली बन गयी है और उसको भी हमने जारी किया है । मैं अधिक डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा । स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दोनों सदनों में घोषणा की । 15 अगस्त को भी उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो जो भी दोषी पाया जाएगा उसको नहीं छोड़ेंगे । स्वयं अपने आप में सदन सर्वोच्च है । दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की जे०पी०सी० का गठन हो चुका है । जो भी खामियां हैं उन को जे०पी०सी० देखेगी । हमारे माननीय सदस्य जो यहां पर स्टेट्युटेरी रेजोल्यूशन लाए हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में कहूंगा ।

The Special Court (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Ordinance, 1992, which was promulgated on 6th June, 1992, requires to be replaced by an Act positively before 18th August, 1992. The Bombay High Court has upheld the constitutional validity of the Ordinance. The Finance Minister has already had a detailed discussion with the leaders of the Opposition parties regarding the amendments. I, therefore, urge the hon. Member to kindly withdraw the Resolution so that the Bill is passed today itself unanimously.

सर, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि इसमें बहुत से मुद्दे यहां पर उठाए गये हैं और इसके साथ साथ स्वयं जे०पी०सी० फिर इस मामले को देखेगी । इसीलिए मैं माननीय सदस्यों से, सबसे निवेदन करूंगा कि सर्वानुमति से इस बिल को पास किया जाए ।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : मैंने राय के बारे में पूछा था । इनके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया ।

श्री दलबीर सिंह : खुद मंत्री जी ने कहा है... (**व्यवधान**) न उनको जानकारी है और ऐसा है कि अगर कोई आपको फैक्ट्स मालूम है तो आप दीजिए । अगर ऐसा होगा तो हम एक्शन लेंगे... (**व्यवधान**)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : राय की क्या प्रगति हुई है... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKOMAL SEN): The mover of the Resolution is not present. It has to be put to vote. The question is:

> "That this House disapproves of the Special Court (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Ordinance, 1992 (No. 10 of 1992) promulgated by the President on the 6th June, 1992."

The Motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKOMAL SEN): I shall now put the motion moved by Shri Dalbir Singh to vote. The question is:

> "That the Bill to provide for the establishment of a Special Court for the trial of offences relating to transactions in securities and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKOMAL SEN): Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 to 15 were asked to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN SHRI SHKOMAL SEN

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI DALBIR SINGH: Sir, I move

That the Bill be passed.

The motion was adopted.

STATEMENTS BY MINISTER

1. Organisation of International Film Festival of India, 1993 at New Delhi

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT KUMAR PANJA): Sir, International Film Festival of India (IFFI) is organised by the Directorate of Film Festivals (DFF) under the Ministry of Information and Broadcasting, every year in the month of January. The IFFI, '87 at New Delhi was the last competitive Film Festival organised by the DFF. All the 5 International Film Festivals which were organised after that were non-competitive events. After the last festival at Bangalore in January, '92, a review was conducted with a view to make the festival attractive and to organise it in a better way so as to fulfil the objectives for which it was designed. In principle, it was decided to organise the next IFFI as a competitive event and this August House was apprised of this decision of the Government in reply to an Unstarred Question No. 3951 on 26.3.1992.

2. I am happy to inform the members that arrangements have already been initiated for organising this International event in Delhi. However, in view of the resource crunch faced by the country in the current financial year and also the tight position in respect of the foreign exchange availability, the matter of making the next IFFI, a competitive event has been reconsidered. The Film Advisory Committee of this Ministry has gone into the matter of revival of the concept of the competitive festival and has recommended that first of all we have to see that all necessary infrastructural facilities become available, since it is the perception of the importance of a festival that attracts the best films and outstanding film personalities. Also, a lead-time of 15—18 months is required by the Directorate of Film Festivals to plan in a systematic manner the organisation of a world class competitive event. In the current scenario, it has been considered prudent to retain the existing character of International Film Festival and to hold it as a non-competitive event at New Delhi in January, 1993.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): It is mentioned in the statement that it was decided by the Government to hold the next IFFI as a competitive event. I am sure the Ministry is already in touch with other nations. Now it is not proper for us at this moment to back out. May I know from the hon. Minister, because it is the prestige of the country which is involved, what is the foreign exchange implication for conducting this competitive Film Festival? I would also like to know why such decision was taken without making available the necessary infrastructural facilities. Sir, when we put an invitation forward and we don't have the necessary infrastructural facilities, we are making a mockery of ourselves. May I know from the hon. Minister as to why the Government made this proposal to hold a competitive Film Festival?

It is also mentioned in the staement that the last competitive Film Festival was held in 1987. That means we have the paraphernalia with us. May I know from the hon. Minister what more paraphernalia is to be added to facilitate this Film Festival?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKOMAL SEN): Shri Digvijay Singh —not present. Shri Syed Sibtey Razi.

श्री सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बंगलौर में जो पिछला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था हमारे तत्वाधान